04 - आने वाले सौ साल सहकारिता के

05 - रंचना प्रधान- विस्थापन और भेदभाव से जूझकर बनाया व्यक्तित्व

A Daily News Magazine

भोपाल

शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025

06 - पुराने अस्पताल की भूमि पर लगेगा राखी बाजार

07 - समाज को नशा और अपराध मुक्त बनाने के लिए प्रदेश...

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 22, अंक 316, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में
जुल्फें सफ़ेद हो गईं उन्नीस साल में
वो ऐसे रो रहा था मेरा हाल देखकर
आया हुआ हो जैसे किसी इंतेक़ाल में
इक बार मुझको अपनी निगेहबानी सौंप दे
उम्रें गुज़ार दूंगी तेरी देखभाल में
ये बात जानती हूं मगर मानती नहीं
दिन कट रहा है आज भी तेरे ख़याल में
वो तो सवाल पूछ के आगे निकल गया
अटकी हुई हूं मैं मगर उसके सवाल में।

- हिमांशी बाबरा

प्रसंगवश

डिफेंस में आत्मनिर्भरता के लिए भारत इजरायल से सीखे सबक

मनोज नरवणे

भारत और इज़रायल करीब एक साल के अंतर पर आज़ाद हुए– भारत अगस्त 1947 में, तो इज़रायल मई 1948 में। आज़ाद होते ही इन दोनों देशों को दुश्मनी पर आमादा अपने पड़ोसियों से अपनी संप्रभुता और भौगोलिक अखंडता की रक्षा के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। नए देशों के रूप में इन दोनों को विरासत में ऐसी अर्थव्यवस्था मिली, जो शैशव काल में थी; इन्फ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर था; भारी उद्योग सीमित आकार में था और सुरक्षा पर खतरा आसन्न था। वास्तव में, इज़रायल की हालत शायद ज्यादा खराब थी क्योंकि 1948 के अरब-इज़रायल युद्ध से जुड़े पक्षों में शामिल होने की वजह से संयुक्त राष्ट्र ने उसे हथियार और फौजी साजोसामान हासिल करने पर पाबंदी लगा रखी थी।

इन प्रतिबंधों और अपने अस्तित्व पर संकट के बावजूद इज़रायल खुद में तेज़ी से बदलाव लाकर रक्षा संबंधी आविष्कारों का 'पावरहाउस' बन गया और 2024 तक आते-आते 15 अरब डॉलर मूल्य के अत्याधुनिक हथियारों का निर्यात करने लगा, लेकिन भारत अपनी ज़रूरतों के लिए हथियारों के आयात पर ही निर्भर बना हुआ। इस फर्क को समझ जाएं तो हमें रणनीति, संस्थागत डिजाइन और राष्ट्रीय संकल्प के बारे में वे प्रमुख सबक मिल जाएंगे जिन्हें सीखना भारत के लिए बेहद ज़रूरी है अगर वह दुनिया में एक महाशक्ति बनना चाहता है।

प्रतिरक्षा के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने का इज़रायल का सफर अस्तित्व रक्षा की ज़रूरत और नए आविष्कार करने की राष्ट्रीय संस्कृति के मेल से प्रेरित था। इसके विपरीत भारत के सैन्य लक्ष्य गुटनिरपेक्षता के दर्शन से निर्धारित हो रहे थे और ज़ोर असैनिक उद्योगों पर दिया जा रहा था।

यह स्थिति खासतौर से नेहरू के दौर में थी, जब सेना को एक ज़रूरी बुराई के रूप में देखा जाता था और एक ठोस सैन्य आधार की कीमत पर असैनिक उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही थी। दूसरी ओर, इज़रायल ने अपने अस्तित्व की खातिर सैन्य ताकत को बढ़ाना ज़रूरी माना। 1948 से लेकर 1967, 1973 और फिलहाल गाज़ा में जारी युद्ध तक हर लड़ाई ने वहां आविष्कारों को उत्प्रेरित करने का काम किया, जिसने युद्धक्षेत्र की मांग पर न केवल नए-नए वेपन सिस्टम का विकास करवाया बल्कि नई सामरिक चालों, तकनीकों और प्रक्रियाओं को भी जन्म दिया।

खास तौर से 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद हमें भी अपनी रक्षा तैयारियों को 'अपग्रेड' की ज़रूरत तेज़ी से महसूस होने लगी है। महत्वपूर्ण कमज़ोरियों को दूर करने के लिए विदेश से सीमित आयात की ज़रूरत भी महसूस होने लगी और विदेश में बने 'फिफ्थ जेनरेशन' के फाइटर विमानों को सेना में शामिल करने की संभावना पर विचार होने लगा है।

इज़रायल ने अपनी सेना, शिक्षा जगत, और निजी औद्योगिक क्षमताओं का संस्थागत मेल किया, जिससे करीबी तालमेल वाली व्यवस्था ने आकार लिया। इजरायल डिफेंस फोर्सेज़ (आईडीएफ) ने विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप कंपनियों और एल्बिट सिस्टम्स, राफेल तथा इज़रायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज (आईएआई) के साथ करीबी तालमेल से काम किया।

तीन सेक्टरों की साझेदारी के कारण प्रोटोटाइपिंग, युद्धक्षेत्र वाले परीक्षण और पुनरावृत्तीय संशोधन में तेज़ी आई। इसके विपरीत भारत का डिफेंस सेक्टर लगभग पूरी तरह अलग-थलग रहा। डीआरडीओ, एचएएल और ओएफबी जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के वर्चस्व के नीचे यह नौकरशाही वाली सुस्ती और सीमित व्यापारिक प्रोत्साहन या जवाबदेही के साथ काम करता रहा। उपभोक्ताओं (सेना) और डिजाइनरों (डीआरडीओ) के बीच कमजोर फीडबैक के अलावा शिक्षा जगत, उद्योग जगत और सेना के बीच तालमेल के लगभग पूरे अभाव ने प्रगति की रफ्तार को और धीमा किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खरीद को न्यूनतम लागत (एल-1) मॉडल से सर्वोच्च प्रदर्शन (टी-1) आकलन मॉडल की ओर बढ़ना चाहिए। लाइफ साइकिल लागत, ऑपरेशन संबंधी प्रदर्शन और देसीकरण से नए आविष्कारों को बढ़ावा मिलेगा और प्रोडक्ट के बदले प्रक्रिया पर ज़ोर देने का चलन हतोत्साहित होगा। एल-1 सिस्टम हमारी खरीद प्रक्रिया का अभिशाप रही है, जिससे कंपनियों में सौदे हासिल करने के लिए न्यूनतम ज़रूरत पूरी करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। इस खेल में सेना के सिवा वास्तव में किसी और का दांव नहीं लगा है।

डिफेंस सेक्टर में निर्यात के मामले में इजरायल की सफलता उसकी रणनीतिक ज़रूरत को भी प्रतिबिंबित करती है। 2024 में इज़रायल के डिफेंस निर्यात के मूल्य ने 14.8 अरब डॉलर के रेकॉर्ड आंकड़े को छू लिया। इसमें 48 फीसदी हिस्सा रॉकेटों, मिसाइलों और एअर डिफेंस सिस्टम्स का था। भारत की सेना बहुत बड़ी है, इसके बावजूद उसका उभरता प्रतिरक्षा उद्योग अपनी क्षमता को बड़े उत्पादन में नहीं बदल पाया है और न वैश्विक बाज़ार में जगह बना पाया है। इस कारण आयातों पर निर्भरता जारी है।

भारत ने इस पैमाने को बदलने के लिए नीतिगत सुधारों की शुरुआत की है। 'मेक इन इंडिया', 'डिफेंस एक्वीजीशन प्रोसिज़र 2020' और 'स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मॉडल' जैसे कार्यक्रम ने डिफेंस सेक्टर के दरवाजे निजी क्षेत्र के लिए खोले हैं, एफडीआई की सीमा में वृद्धि की है और पुराने सरकारी उपक्रमों का कॉर्पोरेटीकरण किया है। गौरतलब है कि रिलायंस डिफेंस ने देश के अंदर ही आधुनिक गोला-बारूद और निर्देशित गोलों का उत्पादन करने के लिए जर्मनी की राइनमेटल और डाएल डिफेंस के साथ हाल में जो साझीदारी की है वह उल्लेखनीय कदम है। इसी तरह देसी हेलिकॉप्टर गनशिप और स्नाइपर राइफल का विकास बताता है कि धीरे-धीरे प्रगति हो रही है। भारत का 100 देशों को डिफेंस निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 21,083 करोड़ रुपये मूल्य का हो गया। इज़रायल की कामयाबी उसके अस्तित्व की ज़रूरत, एकजुट इकोसिस्टम, आविष्कार की संस्कृति और निर्यात आधारित विकास की देन है। भारत को निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि करके, संस्थागत सुधार करके, खरीद पर नए सिरे से विचार करके और मानव पूंजी को बढ़ावा देकर अपनी गति को बढ़ाना चाहिए ताकि डिफेंस में सच्ची आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। इस संदर्भ में फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों के उस भाषण को याद करना उपयुक्त होगा, जो उन्होंने बास्तिले डे 2025 को दिया था। उन्होंने कहा था 'इस दुनिया में आजाद रहना है तो आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि दुनिया आपसे डरे। और इसके लिए आपको ताकतवर बनना बेहद ज़रूरी है।'

भारत के लिए चुनौती यह नहीं है कि उसमें क्षमता नहीं है, उसे एकता और संकल्पबद्धता की जरूरत है। लक्ष्य केंद्रित, उपभोक्ता के अनुकूल डिफेंस इकोसिस्टम तभी हासिल किया जा सकता है, जब सरकार शक्ति दे, सीमाएं न तय करे; सेना नेतृत्व करे, सिर्फ निगरानी न रखे और उद्योग जगत निर्माण करे, सुविधाओं का इंतज़ार न करता रहे। भारत के पास दुनिया का एक सबसे उम्दा देसी डिफेंस इकोसिस्टम तैयार करने के लिए जरूरी प्रतिभाएं, मांग, और माहौल मौजूद हैं। बस इन सबको एकजुट करने की ज़रूरत है।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

मध्यप्रदेश को औद्योगिक और रोजगार सम्पन्न राज्य बनाएंगे : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने किया 6 औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन

● अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में शीघ्र प्रारंभ होगी पुलिस चौकी, महिला अधिकारी भी होंगी पदस्थ ● 15 करोड़ 61 लाख लागत के विस्तारित अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र का हुआ भूमि-पूजन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारे उद्योग और कारखाने मंदिरों की तरह हैं, जो लोगों के कष्ट मिटाते हैं। मध्यप्रदेश में उद्योगों का निरंतर जाल फैलाया जा रहा है। प्रदेश के युवाओं को पलायन की आवश्यकता नहीं है, नए उद्योग शुरू होने से प्रदश में तेजी से समृद्धि आएगी। युवाओं को रोजगारपरक उद्योगों में प्रोत्साहन देते हुए 5 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। मध्यप्रदेश को औद्योगिक और रोजगार संपन्न राज्य बनाएंगे और मध्यप्रदेश देश का नंबर एक राज्य होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री

डॉ. यादव गुरूवार को भोपाल के निकट अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में 416 करोड़ रूपये निवेश वाली 6 नवीन औद्योगिक इकाईयों के भूमि-पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अचारपुरा विशेष औद्योगिक केन्द्र

के रूप में उभरेगा। उन्होंने अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र एक्सटेंशन फेज-3 (ग्राम हज्जामपुर) का शिलान्यास भी किया, जो 31.21 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में दुनिया के बड़े-बड़े उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए आ रहे हैं। अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में आज हर पीढ़ी के उद्यमी हैं। जहां गोकलदास एक्सपोर्टस प्रा.लि. के श्री प्रभात सिंह उपस्थित हैं वहीं सिनाई हेल्थकेयर के युवा श्री आदित्य शर्मा और एसेड्स प्राइवेट लिमिडेट के श्री रौनक चौधरी की उपस्थिति प्रसन्नता प्रदान कर रही है। अचारपुरा की तस्वीर बदल गई है। सावन का समय है और यहां उद्योगों की वर्षा हो रही है।

गोकुलदास एक्सपोर्ट्स 2 इकाई लगाकर 2500 बहनों को देगा रोजगार

गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के डायरेक्टर श्री प्रभात सिंह ने कहा कि कंपनी देशभर में 36 इकाइयाँ संचालित कर रही है, जिनमें से एक कीनिया में भी स्थित है। वर्तमान में उनकी इकाई में 2500 महिलाएं कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि अचारपुरा क्षेत्र में एक और इकाई स्थापित करने जा रहे हैं, जहां लगभग 2500 बहनों को और रोजगार मिलेगा। श्री सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश का निवेश फ्रेंडली वातावरण, निवेशक-हितैषी नीति और मजबूत औद्योगिक ईकोसिस्टम उन्हें इस क्षेत्र में और अधिक फैक्ट्रियाँ स्थापित करने के लिए प्रेरित कर रहा है। प्रवेश में अधिक से अधिक इंडस्ट्री स्थापित करेंगे।

सिंगल विंडो के माध्यम से सभी अनुमतियों का तुरंत मिल जाना सराहनीय -सिनाई हेल्थ केयर के डायरेक्टर श्री आदित्य शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के सतत प्रयासों से मध्यप्रदेश में निवेश का सकारात्मक वातावरण बना है। श्री शर्मा ने भूमि आवंटन से लेकर सभी अनुमतियों के मिलने की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बताया और मुख्यमंत्री एवं उनकी टीम को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अचारपुरा में 120 करोड़ रु. के निवेश से सिनाई हेल्थ केयर इंडस्ट्री स्थापित की जाएगी।

सर्पदंश की घटनाएं हमारे लिए चुनौती : सीएम

प्रदेश में सांपों के काटने से हो रहीं सर्वाधिक मौतें; रोकने के उपाय करें

वन विकास निगम ने वन सम्पदा को पुर्नस्थापित किया

जोधपुर से आम और बबूल का फर्नीचर हो रहा एक्सपोर्ट

सीएम ने कहा, अच्छे कामों को केंद्र सरकार भी प्रोत्साहित करती है। निवेश को लेकर हमारे राज्य की वन संपदा की जो नीलामी करते हैं। तो हम जोधपुर गए थे मैंने कहा था कि फर्नीचर कलस्टर का जहां भी निर्यात होता है। हमें लगा कि हमारे यहां बहुत बड़ी इमारती लकड़ी है उन्नत श्रेणी का सागौन है लेकिन पूरे देश में सबसे ज्यादा निर्यात राजस्थान के जोधपुर से होता है।

हम सागौन का फर्नीचर देंगे तो दुनिया पागल हो जाएगी

सीएम ने कहा- हमने जोधपुर में पूछा तो उन्होंने बड़ी चौंकाने वाली बात बताई कि आपके यहां जो है वो है।

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में खनन गतिविधियों और बिजली उत्पादन की प्रक्रिया में बने राख के पहाड़ों पर वनों को विकसित करने की चुनौती स्वीकार कर मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम ने वन सम्पदा को पुर्नस्थापित किया है। प्रदेश के तीन लाख 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वनों का पुनर्वास करना बड़ी उपलब्धि है। वन विकास निगम इस उपलब्धि के लिए बधाई का पात्र है। यह गर्व का विषय है कि अन्य राज्य भी निगम की इस विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए उत्सुक हैं। प्रदेश में अद्यतन तकनीक के माध्यम से वनों का उचित प्रबंधन किया जा रहा है।

सीएम ने कहा- वन विकास निगम को महाराष्ट्र में भी काम मिल रहा

सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, किसी भी निगम की 50 साल की यात्रा हमारे लिए गौरवपूर्ण है। हमारे निगम को न केवल बल्कि महाराष्ट्र में भी काम मिल रहा है। आपने दूरगामी दृष्टि से अच्छी छलांग लगाने का काम किया है। निगम में जो संभावनाएं हैं, उसे और टटोला जाए। जब हम 50 साल के मुकाम तक पहुंचते हैं तो सिंहावलोकन करते हुए पुरानी व्यवस्थाओं के आधार पर अगली छलांग और बड़ी लगाने का संकल्प लेने की जरूरत है।

चीन सीमा के पास क्रैश हो गया रूस का विमान

● सभी 49 लोगों की मौत, तलाशी में दिखा मलबा

मास्को (एजेंसी)। रूस का एक यात्री विमान चीन की सीमा के पास क्रैश हो गया है। हादसे में विमान में सवार 49 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 43 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। यात्रियों में 5 बच्चे भी शामिल थे। बचावकर्मियों को टिंडा से लगभग 16 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर रूसी यात्री विमान का मलबा मिला है। रॉयटर्स के मुताबिक ये विमान रूस के पूर्वी अमूर क्षेत्र में उड़ रहा था। अमूर के गवर्नर वासिली ओरलोव ने टेलीग्राम पर बताया कि लापता विमान अंगारा एयरलाइंस का है। लोकल इमरजेंसी मिनिस्ट्री ने बताया कि विमान खाबरोवस्क, ब्लागोवेशचेंस्क होते हुए टिंडा जा रहा था।

भारत और यूके के बीच हो गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट

पीएम मोदी बोले-कई साल की मेहनत के बाद हुआ समझौता

लंदन (एजेंसी)। भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पर आखिरकार हस्ताक्षर हो गए हैं। इसका मतलब है कि अब दोनों देशों के बीच चीजों का लेन-देन और व्यापार पहले से आसान और सस्ता हो जाएगा। फ्री ट्रेड डील के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। इस डील से न सिर्फ सामान सस्ते होंगे, नौकरियां बढ़ेंगी और दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। इस डील के बाद भारतीय बाजार में यूके से आने वाले सामान सस्ते होंगे, जबकि भारत से होने वाले निर्यात में बड़ी छलांग लगने की उम्मीद है। दोनों देशों के कारोबारियों और विशेषज्ञों ने इस समझौते का स्वागत किया है। अधिकारियों ने कहा कि एफटीए के लागू होने पर 99 प्रतिशत भारतीय निर्यात पर ब्रिटेन में शुल्क नहीं लगेगा।

भारत के लिए गेमचेंजर होगी यह फ्री ट्रेड डील

भारत के लिए यह डील कई मायनों में गेमचेंजर मानी जा रही है। समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को 99 फीसदी उत्पादों पर ब्रिटेन में ड्यूटी-फ्री एंट्री मिलेगी। इससे लगभग 23 अरब डॉलर के व्यापार अवसर खुलने का अनुमान है। सरकार के मुताबिक, इससे भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे कपड़ा, चमड़ा, जूते, गहने, खिलौने और समुद्री उत्पादों में काम करने वाले कारीगरों, बुनकरों और दैनिक मजदूरों को सीधा फायदा होगा। लघु सेक्टर की लाखों इकाइयों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस समझौते से 95 फीसदी कृषि उत्पाद अब बिना किसी शुल्क के ब्रिटेन में निर्यात किए जा सकेंगे।

● नॉर्थ ब्लॉक से शिफ्टिंग की प्रक्रिया हो गई है शुरू

बहुत जल्द बदलने वाला है गृह मंत्रालय

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्रालय का पता रायसीना हिल्स, नॉर्थ ब्लॉक से जल्द ही बदलने वाला है। इसे जनपथ में बनी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत सभी मंत्रालयों के लिए कर्तव्य पथ पर 10 ऑफिस बिल्डिंग और एक कन्वेंशन सेंटर

समेत सीसीएस बनना है। इनमें से तीन बिल्डिंग लगभग बन चुकी हैं। धीरे-धीरे अन्य ऑफिस भी यहां से सीसीएस शिफ्ट किए जाएंगे। अभी नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा, गृह, विदेश और वित्त मंत्रालय जैसे कई अहम ऑफिस हैं। सभी ऑफिस शिफ्ट होने के बाद दोनों ब्लॉकों को युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय में बदल दिया जाएगा। इसमें करीब 25 से 30 हजार कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। यह दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम्स में से एक होने की संभावना है। करीब 90 सालों से देश का गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक से ही संचालित हो रहा था। नए कॉम्प्लेक्स में गृह मंत्रालय के लिए 347 कमरे केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने वाले पहले अधिकारियों में से हैं।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 35 °c | न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शुक्रवार, 25 जुलाई 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

उत्तर प्रदेश की सबसे ताकतवर गद्दी के लिए काउंट डाउन शुरू

- मिलेगा एक्सटेंशन या आएगा नया चेहरा, सबकी हैं निगाहें

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी में अगले विधानसभा चुनाव (2027) में अभी भले वक्त हो, लेकिन सबसे ताकतवर नौकरशाही गद्दी यानी मुख्य सचिव पद पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसको लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों जबरदस्त हलचल है। मौजूदा मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त हो रहा है। बड़ा सवाल सबके सामने है कि क्या सीएम

योगी के करीबी मनोज कुमार सिंह को सेवा विस्तार मिलेगा या फिर कोई नया चेहरा इस पद को संभालेगा। फिलहाल अगला मुख्य सचिव कौन होगा, इसको लेकर योगी सरकार की साख भी दांव पर है। मुख्य सचिव का पद केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि मुख्यमंत्री और सरकार के सुचारु संचालन का सबसे अहम आधार होता है। ऐसे में यह तय करना कि अगले दिनों में इस गद्दी पर कौन बैठेगा, योगी सरकार और केंद्र के लिए बेहद अहम निर्णय बन चुका है। मनोज कुमार सिंह 1988 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद विश्वस्त अफसर माने जाते हैं।

बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर संसद में संग्राम

- विपक्ष की नारेबाजी, सिर्फ 12 मिनट चली कार्यवाही

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद के मानसून सत्र का गुरुवार को चौथा दिन था। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले पर हंगामा करने लगे। कांग्रेस सहित कई विपक्षी सांसद वेल में आकर पोस्टर लहराने लगे। स्पीकर ओम बिरला ने कहा- तख्तियां लेकर आने पर सदन नहीं चलेगा। उन्होंने कांग्रेस सांसदों से कहा- ये आपके संस्कार नहीं हैं।

हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही आज सिर्फ 12 मिनट चल सकी। इसे शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही सिर्फ 1.45 मिनट चल पाई। उधर संसद के बाहर मकर द्वार पर बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले पर लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन किया गया। सोनिया गांधी भी इसमें शामिल हुईं। प्रियंका गांधी ने खतरे में लोकतंत्र लिखा पोस्टर लहराया। राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं ने बिहार में एसआईआर मुद्दे पर सदन में हंगामा किया। जिसके बाद सदन को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने फिर हंगामा कर दिया।

दहेज, प्री-वेडिंग शूट पर रोक, आसान होगी घरवापसी

- 356 पन्ने की हिंदू आचार संहिता अक्टूबर में होगी सार्वजनिक
- काशी विद्वत परिषद ने किया तैयार, समाज में संतुलन है उद्देश्य

वाराणसी (एजेंसी)। महाकुंभ में संतों की बैठक में हिंदू आचार संहिता को लेकर मंथन हुआ था। अब काशी विद्वत परिषद के मुताबिक अक्टूबर 2025 में सार्वजनिक होगी। पहले चरण में 356 पेज की आचार संहिता की एक लाख प्रतियां छपवाई और हिंदुओं के घर-घर तक पहुंचाई जाएंगी। इसके जरिये समाज को बांटने वाले लोगों को कड़ा संदेश दिया जाएगा।

पहले चरण में इसकी एक लाख प्रतियां छपवाकर देशभर के हिंदू घरों तक पहुंचाने की योजना है। इस 356 पेज की संहिता में दहेज प्रथा पर पूरी तरह रोक लगाने का प्रावधान है। शादियों में केवल कन्यादान की अनुमति होगी और विवाह वैदिक रीति से दिन में कराने की सिफारिश की गई है। साथ ही मंदिरों के गर्भगृह में केवल अर्चकों को प्रवेश की अनुमति देने की बात कही

गई है। संहिता में महिलाओं को धार्मिक अधिकार देने पर विशेष जोर दिया गया है। महिलाएं अब यज्ञ और हवन जैसे अनुष्ठानों में भाग ले सकेंगी। कन्या भ्रूण हत्या को पाप घोषित किया गया है। साथ ही, 'घर वापसी' की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए इसमें स्पष्ट किया गया है कि ब्राह्मण शुद्धिकरण के बाद व्यक्ति को नया गोत्र भी देंगे।

कृपया ध्यान दें!

केवायसी नहीं कराई तो बंद हो जाएगा आपका राशनकार्ड

- अब हर पांच साल में कराना होगा जरूरी, वरना नहीं मिलेगा लाभ

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने बुधवार को मौजूदा पीडीएस नियमों में संशोधन करते हुए सभी राशन कार्ड धारकों के लिए हर पांच साल में इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर यानी ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में धोखाधड़ी को रोकना, डुप्लिकेट कार्ड्स को हटाना और सब्सिडी को सही लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना है। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बुधवार को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 के तहत

पीडीएस में पारदर्शिता बढ़ाने, डुप्लिकेशन को रोकने और सब्सिडी के टारगेट को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके तहत, राज्य सरकारों को सभी पात्र परिवारों के लिए हर पांच साल में ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। इस प्रक्रिया में अयोग्य परिवारों को लाभार्थी सूची से हटाया जाएगा और नवीन पात्र परिवारों को शामिल किया जाएगा। नए नियमों के अनुसार, अलग राशन कार्ड के लिए न्यूनतम आयु अब 18 वर्ष निर्धारित की गई है। यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि केवल पात्र व्यक्ति ही राशन कार्ड के माध्यम से सब्सिडी प्राप्त करें। कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले अलग राशन कार्ड रखने का पात्र नहीं होगा। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के आधार नंबर (अगर उपलब्ध हैं) एकत्र किए जाने चाहिए और उनके पांच साल का होने के एक वर्ष के भीतर ई-केवाईसी करवाना आवश्यक है। अधिसूचना में कहा गया है, जिन लाभार्थियों ने पिछले छह महीनों में अपने अधिकारों का लाभ नहीं उठाया है, उनके राशन कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। राज्य सरकार को पात्रता का पुनर्मूल्यांकन करने और आगे की कार्रवाई करने के लिए तीन महीने के भीतर क्षेत्रीय सत्यापन और ई-केवाईसी पूरा करना होगा।

संघ प्रमुख भागवत की मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बड़ी बैठक

- महासचिव होसबाले, इमाम चीफ उमर अहमद रहे मौजूद

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार को दिल्ली के हरियाणा भवन में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की।

संघ की टॉप लीडरशिप की 70 से ज्यादा मुस्लिम धर्मगुरुओं, बुद्धिजीवियों, मौलानाओं और स्कॉलर से मुलाकात हुई। इस बैठक में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद और आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले, सह सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल, राम लाल, इंद्रेश कुमार सहित आरएसएस के अन्य पदाधिकारी शामिल हुए हैं।

इससे पहले सितंबर 2022 में मोहन भागवत ने कई मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात की थी। बैठक में ज्ञानवापी विवाद, हिजाब विवाद और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी। इस दौरान भागवत दिल्ली के एक

मस्जिद में भी गए थे। दरअसल, संघ अपनी सहयोगी संस्था मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जरिए मुस्लिम मौलवियों, धर्मगुरुओं और समुदाय के प्रमुख लोगों के साथ बातचीत करता है। 2023 में आरएसएस ने कहा था- वह एक राष्ट्र, एक झंडा, एक राष्ट्रगान के लिए पूरे देश में अभियान चलाएगा। सितंबर 2021 में मुस्लिम विद्वानों के एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था- भारत में रहने वाले हिन्दुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक समान हैं। मुस्लिमों को भारत में डरने की जरूरत नहीं है। हमें भारत वर्चस्व की सोच रखनी होगी।

धर्मांतरण केस में बढ़ रहीं छांगुर बाबा की मुश्किलें

- एटीएस और ईडी की जांच में चौकाने वाला खुलासा

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। यूपी एटीएस और ईडी की जांच में लगातार बड़े-बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच मिल रही जानकारी के मुताबिक, छांगुर बाबा ने विदेश से मिले फंड से प्रदेशभर में बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी है। यही नहीं, इन जमीनों पर प्लॉटिंग और निर्माण कार्य भी कराया गया, जिनके जरिए मतांतरण की साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। प्रदेश के 300 से ज्यादा रजिस्ट्री कार्यालयों में छांगुर और उसके सहयोगियों के नाम से दर्ज रजिस्ट्री दस्तावेजों की पड़ताल शुरू हो गई है। इन सभी लोगों की सूची बनाकर सभी उपनिबंधकों को भेज दी गई है और उनके नाम पर दर्ज बैनामों का विवरण मांगा गया है।

अनिल अंबानी की पचास कंपनियों पर ईडी की रेड!

मुंबई (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें करीब 50 कंपनियों शामिल है। 25 से ज्यादा लोगों से भी पूछताछ की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यस बैंक से लिए 3000 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में गुरुवार, 24 जुलाई को की गई ये रेड दिल्ली और मुंबई में चल रही है। ये छापेमारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 17 के तहत की जा रही है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ये कार्रवाई सीबीआई की ओर से दर्ज दो एफआईआर और सेबी, नेशनल हाउसिंग बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर की गई है।

हिमाचल में यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 7 की मौत

- 27 से ज्यादा लोग घायल, सीएम ने जताया शोक

मंडी (एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश के मंडी में गुरुवार सुबह हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। 27 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। एसपी मंडी ने इसकी पुष्टि की है। मृतकों में 4 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। घायलों को स्थानीय पुलिस व ग्रामीणों की मदद से खाई से निकालकर सरकाघाट अस्पताल पहुंचाया गया।

गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को एम्स बिलासपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि बस गुरुवार सुबह करीब 9 बजे सरकाघाट से दुर्गापुर जा रही थी और करीब पौने 10 बजे सरकाघाट-जमनी-दुर्गापुर सड़क पर मसेरन तालगरा के पास अचानक बस बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को हादसे की जानकारी दी और खुद भी राहत एवं बचाव कार्य में जुटे। अब तक की जानकारी के अनुसार, बस में 30 से 35 यात्री सवार थे। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक सूचना के अनुसार, यह हादसा तीखे मोड़ पर ड्राइवर द्वारा बस पर नियंत्रण खोने से हुआ है।

रेणुकास्वामी मर्डर केस

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट को दोबारा फटकारा

- आरोपी ऐक्टर दर्शन को जमानत देने पर कहा-अदालत ने पावर का गलत इस्तेमाल किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा को जमानत देने के फैसले पर दूसरी बार फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट ने रेणुकास्वामी मर्डर केस में ज्यूडिशियल पावर का गलत इस्तेमाल किया है। इससे पहले 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से एक्टर दर्शन को मिली जमानत पर सवाल उठाए थे। इस दौरान कहा था कि लगता है हाईकोर्ट ने अपने विवेक का सही इस्तेमाल नहीं किया। फिलहाल सुप्रीम

कोर्ट ने एक्टर की जमानत रद्द करने का फैसला सुरक्षित रखा है। दरअसल, एक्टर दर्शन को रेणुकास्वामी मर्डर केस में 13 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, जिसके बाद वो जेल से रिहा हुए थे। इसी के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को मार्च में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने गुरुवार को कहा- वे हाईकोर्ट वाली गलती नहीं करेंगे।

मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस

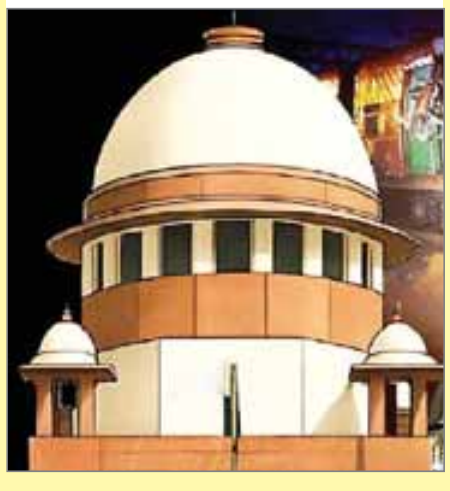

हाईकोर्ट के फैसले पर 'सुप्रीम' रोक

- तीन दिन पहले 12 आरोपियों को कर दिया था बरी
- एससी बोला-फिलहाल दोबारा जेल भेजना जरूरी नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर गुरुवार को रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से आरोपियों की जेल से रिहाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ट्रेन ब्लास्ट केस में 13 लोग आरोपी थे। 12 सभी रिहा हो गए हैं। एक आरोपी की मौत हो गई है। बता दें कि वर्ष 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले

में सभी 12 अभियुक्तों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की थी। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले के सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया और राज्य सरकार द्वारा दायर अपील पर उनसे जवाब मांगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को मिसाल नहीं माना जाएगा। सोमवार को न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की विशेष हाईकोर्ट पीठ ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा और यह विश्वास करना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है। विशेष अदालत ने 12 में से पांच को मौत की सजा और सात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मौत की सजा पाए एक दोषी की 2021 में मौत हो गई। 11 जुलाई 2006 को मुंबई लोकल ट्रेनों में सात विस्फोट हुए थे।

पुलिस ट्रेनिंग में नए आरक्षक रामायण पढ़ें

एडीजी का फरमान-ट्रांसफर मांगने पर दी सलाह, कांग्रेस को आपत्ति, कॉन्स्टेबल बोले- मन को शांति मिलेगी

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश पुलिस भर्ती में नए कॉन्स्टेबल ट्रेनिंग के दौरान रामायण पाठ करेंगे। ये सलाह पुलिस मुख्यालय के एडीजी (प्रशिक्षण) राजाबाबू सिंह ने दी है। पुलिस में सिलेक्ट होकर आए नए जवान इस सुझाव को अच्छा मान रहे हैं। वहीं, विपक्षी दल कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी ने कहा, देश संविधान से चलेगा और भारत का संविधान सर्व धर्म समभाव और धर्मनिरपेक्ष है। पुलिस मुख्यालय से कॉन्स्टेबल ट्रेनिंग के लिए जो निर्देश जारी किए गए हैं कि एक धर्म विशेष का धार्मिक ग्रंथ पढ़ाया जाए। इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है। सरकार का कोई धर्म और जाति नहीं है। इस देश में सभी धर्मों का बराबरी से सम्मान होता है। किसी को भी कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए बाध्य न किया जाए।

रामजी के वनवास के आगे ये ट्रेनिंग कुछ भी नहीं- ट्रेनिंग ले रही कॉन्स्टेबल उस्मानी शबनम ने कहा, साहब ने बताया कि राम जी ने किस तरह 14 साल का वनवास लिया था। उसके सामने तो ये पुलिस ट्रेनिंग कुछ भी नहीं है। इससे हमें सीख लेना चाहिए कि परिवार से दूर रहकर हम भी देशभक्ति कर सकें। रामचरितमानस का पाठ करने से हमें रामजी के आचरण पर चलने और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहने की सीख मिलेगी।

- **रामायण पाठ करने से हम मोटिवेटेड रहेंगे-** कॉन्स्टेबल अयान महमूद खान ने कहा, राम जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। यहां अच्छे से ट्रेनिंग करके निकलेंगे और देश की सेवा करेंगे।

एडीजी बोले- कॉन्स्टेबलों के कोर्स में संशोधन किया

मध्यप्रदेश पुलिस में आरक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए कुल 8 ट्रेनिंग सेंटर हैं। पीटीएस रीवा, उमरिया, पचमढ़ी (नर्मदापुरम), इंदौर, उज्जैन, भौंरी (भोपाल), तिघरा (ग्वालियर) और सागर। यहां 23 जुलाई से 4 हजार नव आरक्षकों की ट्रेनिंग शुरू हुई है। ट्रेनिंग 9 महीने की होगी। 1 जुलाई 2024 को न्यू क्रिमिनल लॉ लागू हो गए हैं। इसी को देखते हुए हमने पुलिस कॉन्स्टेबल के बेसिक कोर्स में संशोधन किया है।

रामचरित मानस पढ़ने का अच्छा सुझाव दिया है। इससे हम मोटिवेटेड रहेंगे और हमारा मन शांत रहेगा। दिन भर की थकान के बाद अगर हम शाम को इसका पाठ करते हैं तो हमें मेंटली पीस मिलेगा। एडीजी सर का अच्छा सजेशन है, हम लोग भी इसे ट्राय करेंगे।

- **ट्रेनिंग से एक दिन पहले की कॉन्स्टेबलों से बात-** बुधवार 23 जुलाई से मप्र के आठ पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों में करीब 4 हजार नए पुलिस आरक्षकों की ट्रेनिंग शुरू हुई। जून में पुलिस की नौकरी में चयनित होकर आए करीब 600 आरक्षकों ने अपने गृह जिले के करीब वाले पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में तबादला करने के आवेदन दिए। बड़ी संख्या में जब नए आरक्षकों की ट्रेनिंग के पहले ही तबादलों के आवेदन और सिफारिशें आईं तो एडीजी ने प्रशिक्षण शुरू होने एक दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इसके जरिए सभी आठ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के एसपी और नए कॉन्स्टेबलों से बात की।
- **ट्रांसफर एप्लिकेशन से परेशान होकर दी सलाह-** एडीजी (प्रशिक्षण) राजाबाबू सिंह ने बताया, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर (पीटीएस) चेंज करने के लिए बहुत सारे एप्लिकेशन आ रहे थे। पीटीएस बदलवाने के लिए भीड़ लगी हुई थी। ज्यादातर एप्लिकेशन में लिखा है- छिंदवाड़ा का रहने वाला हूं, मुझे पीटीएस पचमढ़ी में कर दिया जाए।

मैं चंबल का रहने वाला हूं, पीटीएस तिघरा कर दिया जाए। कोई कह रहा था मां बीमार तो किसी के पिता बीमार हैं। मंगलवार को एडीजी राजाबाबू सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ट्रेनिंग लेने पहुंचे कॉन्स्टेबलों से कहा, भगवान राम ने 14 साल का वनवास स्वीकार किया था। भगवान जब माता-पिता की आज्ञा मानने के लिए 14 साल वन में रह सकते हैं तो आप अपने ट्रेनिंग के लिए घर-परिवार से दूर नहीं रह सकते।

ट्रेनिंग सेंटर चेंज करने का टाइम नहीं

रामायण का पाठ करने के सुझाव पर जब एडीजी राजाबाबू सिंह से बात की तो उन्होंने कहा, अब टाइम नहीं कि ट्रेनिंग सेंटर को चेंज करें। कमिटमेंट के साथ ट्रेनिंग पूरी करें। 9 महीने बाद जब ट्रेनिंग करके निकलेंगे तो कॉन्स्टेबल बदले हुए होंगे। अगले 33 से 35 साल तक मप्र पुलिस का फंट फेस होंगे। इसलिए मैंने भगवान राम का उदाहरण दिया। कहा कि रामचरितमानस पढ़िए और उससे प्रेरणा लीजिए। विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) राजाबाबू सिंह का कहना है कि अब ट्रेनिंग सेंटर बदलने का टाइम नहीं है।

जूनियर डॉक्टरों को सिखाई जा रही जीवन रक्षक तकनीक

- **गांधी मेडिकल कॉलेज में बीएलएस-एसीएलएस प्रशिक्षण, जिससे आपात स्थिति में बचा सकें जीवन**

भोपाल (नप्र)। अक्सर अचानक गश खाकर गिरने वाले लोगों की जान समय पर चिकित्सीय सहायता न मिलने के कारण चली जाती है। ऐसे मामलों का मुख्य कारण 'सडन कार्डियक अरेस्ट' होता है। लेकिन अगर आसपास मौजूद कोई व्यक्ति तुरंत सीपीआर (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) दे दे, तो जिंदगी बच सकती हैं। इसी जागरूकता और आपातकालीन चिकित्सा कौशल को बढ़ाने के लिए गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल में गुरुवार को बीएलएस-एसीएलएस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, मध्यप्रदेश के अध्यक्ष डॉ. कुलदीप गुप्ता ने बताया कि यह कार्यक्रम गांधी मेडिकल कॉलेज की अधिष्ठाता डॉ. कविता एन. सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का नेतृत्व निश्चेतना विभागाध्यक्ष डॉ. आरपी कौशल और डॉ. दीपेश गुप्ता द्वारा किया जा रहा है।

प्रशिक्षण में अलग-अलग विभागों के जूनियर डॉक्टरों को शामिल किया गया है। बीएलएस (बेसिक लाइफ सपोर्ट) और एसीएलएस (एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट) जैसी तकनीक आपात स्थिति में मरीज को तुरंत सहायता देने और उसकी जान बचाने के लिए अत्यंत जरूरी हैं। डॉ. गुप्ता ने कहा, आकस्मिक स्थितियों में त्वरित और सही प्रतिक्रिया ही मरीज की जान बचा सकती है। ऐसे प्रशिक्षण डॉक्टरों की आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में दक्षता बढ़ाते हैं।

पश्चिम मध्य रेलवे में मनीष तिवारी बने नए पीसीसीएम, संभाला पदभार

- **यात्री सेवा से लेकर मालभाड़े तक व्यापक सुधार की तैयारी**

भोपाल (नप्र)। पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय में गुरुवार को वरिष्ठ रेल अधिकारी मनीष तिवारी ने प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (पीसीसीएम) का कार्यभार संभाल लिया। भारतीय रेलवे यातायात सेवा (आईआरटीएस) के 1994 बैच के अधिकारी तिवारी इससे पहले रेलवे बोर्ड, गृह मंत्रालय और उत्तर रेलवे सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मनीष तिवारी ने पश्चिम मध्य रेलवे की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय से शिष्टाचार भेंट की। इसके बाद वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर यात्री सेवाओं, पार्सल, पार्किंग, कैटरिंग और माल भाड़ा बढ़ाने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मनीष तिवारी को वाणिज्य क्षेत्र में गहरा अनुभव है। उनके नेतृत्व में वाणिज्यिक योजनाओं को नई दिशा मिल सकती है। खासकर यात्री सुविधा और राजस्व वृद्धि के मोर्चे पर रेलवे को मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है।

इन अहम पदों पर दे चुके हैं सेवाएं

गृह मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव
रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक (पी.जी.)
उत्तर रेलवे में मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (यात्री सेवा)
पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा मंडल में मंडल रेल प्रबंधक

मुख्यमंत्री डॉ. यादव भोपाल में अत्याधुनिक सी.टी. स्कैन एवं एम.आर.आई. सेवाओं का करेंगे लोकार्पण

मशीनें फास्ट स्क्रीनिंग में सक्षम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शोध भी किया जा सकेगा

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार प्रदेशवासियों को आधुनिक, सुलभ और सर्वसमावेशी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। चिकित्सा शिक्षा एवं जनस्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित कर सर्वसुलभ और अधिक सक्षम बनाने की दिशा में सरकार सतत कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में अत्याधुनिक तकनीकी से युक्त सी.टी. स्कैन मशीन (80 रो डिटेक्टर एक्वारिंग 128 स्लाइस) तथा एम.आर.आई. मशीन (1.5 टेसला) का 25 जुलाई को लोकार्पण करेंगे। उल्लेखनीय है कि यह सुविधा प्रदेश के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में सर्वप्रथम भोपाल में प्रारंभ की गई है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल की गरिमामयी उपस्थिति भी रहेगी।

चिकित्सा छात्रों को बेहतर शिक्षा और शोध कार्यों को मिलेगी गति- इन आधुनिकतम मशीनों से आयुष्मान भारत योजना एवं अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत आने वाले मरीजों को नि:शुल्क सी.टी. स्कैन एवं एम.आर.आई. जाँच की सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं पहुंच को और अधिक मजबूती प्राप्त होगी। इन मशीनों की स्थापना से चिकित्सा छात्रों यू.जी., पी.जी. एवं पैरामेडिकल को बेहतर शैक्षणिक अवसर मिलेंगे, साथ ही शोध कार्यों को भी गति मिलेगी। साथ ही, प्रदेश की जनता को उच्च गुणवत्ता की वे जाँच सुविधाएं अब भोपाल में ही मिल सकेंगी। इसके लिए पूर्व में अन्य राज्यों में जाना पड़ता था। मशीनों के संचालन हेतु प्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ की उपलब्धता भी शासन द्वारा सुनिश्चित की गई है।

इन मशीनों में हाई-क्वालिटी कार्डियक पैकेजेस शामिल हैं, जिनसे हृदय रोगों की उन्नत और सटीक जाँच संभव है। एम.आर.आई. मशीन में डेडीकेटेड ब्रेस्ट कॉइल्स सहित उच्च गुणवत्ता की सभी आवश्यक कॉइल्स प्रदाय की गई हैं, जिससे स्तन कैंसर की गहन जांच सरलता से की जा सकेगी। सी.टी. स्कैन मशीन वॉल्यूमेट्री, फ्यूजन एवं परफ्यूजन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित है, जिससे तीव्र एवं गहन जांच संभव है।

नर्सिंग छात्रा के साथ फ्लैट में बंधक बनाकर रेप

- **सीनियर छात्र ने बर्थ डे सेलिब्रेशन के नाम पर बुलाया; जान से मारने की धमकी दी**

भोपाल (नप्र)। भोपाल के अवधपुरी में एक फ्लैट में नर्सिंग छात्रा के साथ सीनियर छात्र ने रेप किया। घटना मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात की है। बुधवार की रात को पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। आरोपी युवक पीड़िता का सीनियर है। लड़की के बर्थ डे को सेलिब्रेट करने के नाम पर उसे फ्लैट में बुलाकर डरा धमकाकर रेप किया गया है। आरोपी की अभी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। टीआई रतनलाल सिंह परिहार ने बताया कि (21) वर्षीय पीड़िता बागसेवनिया इलाके में रहती है। वह बीएससी क्लिनिक रिसर्च (नर्सिंग) प्रथम वर्ष की छात्रा है। रायसेन रोड पर उसका प्राइवेट कॉलेज है। इसी कॉलेज में राहुल मिश्रा नाम का युवक उसका सीनियर है। कई बार राहुल कॉलेज के छोटे मोटे कामों में उसकी मदद करता था। इसी कारण दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई।

दोस्तों को दूसरे कमरे में भेजा, फिर रेप किया- दो दिन पहले लड़की का जन्मदिन था। आरोपी ने पीड़िता के जन्मदिन को सेलीब्रेट करने के नाम पर उसे फ्लैट पर बुलाया। यहां उसके अन्य दोस्त पहले से मौजूद थे।

देर रात केक कटिंग करने के बाद में आरोपी ने अपने साथियों को फ्लैट के दूसरे रूम में जाने के लिए कह दिया। पीड़िता को एक बेड रूम में लेकर पहुंचा और यहां उसके साथ जबरन रेप किया।

विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी- विरोध करने पर लड़की को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता को स्वयं उसके घर तक छोड़कर आया। बुधवार को फरियादी अपने साथियों के साथ थाने में शिकायती आवेदन लेकर आई।

ई-रिक्शा प्रतिबंध के खिलाफ आप का विरोध प्रदर्शन

भोपाल में ई-रिक्शा रैली निकाली; जहांगीराबाद-जिंसी रोड पर डेढ़ घंटे तक लगा जाम

भोपाल (नप्र)। राजधानी में ई-रिक्शा चालकों पर लगे प्रतिबंधों के विरोध में आज आम आदमी पार्टी (आप) की जिला इकाई के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। 'रिक्शा रैली' के रूप में आयोजित इस विरोध में बड़ी संख्या में ई-रिक्शा चालक शामिल हुए। रैली जिंसी धर्म कांटा से शुरू होकर जहांगीराबाद रूट होते हुए कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़ी।

विरोध प्रदर्शन के चलते जहांगीराबाद चौराहा, जिंसी रोड और सबन चौराहा सहित आसपास के इलाकों में करीब डेढ़ घंटे तक भारी जाम की स्थिति रही। ट्रैफिक जाम के कारण स्थानीय लोगों और स्कूल-ऑफिस जा रहे नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस प्रशासन लगातार यातायात सुचारु करने की कोशिशों में जुटा रहा।

आप के प्रदेश मीडिया प्रभारी मिन्हाज आलम ने कहा कि यह केवल ट्रैफिक का मुद्दा नहीं, बल्कि हज़ारों ई-रिक्शा चालकों की रोज़ी-रोटी से जुड़ा मसला है। बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए प्रशासन द्वारा मुख्य मार्गों से ई-रिक्शा हटाना अन्यायपूर्ण है।

फिलहाल भोपाल में करीब 11,000 ई-रिक्शा संचालित हैं, जिनमें से अधिकांश के पास परमिट नहीं है। ट्रैफिक पुलिस ने लिंक रोड नंबर-1, वीआईपी रोड और बोट क्लब पर ई-रिक्शा की आवाजाही पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध 23 जुलाई से ट्रायल फेज के तौर पर एक सप्ताह के लिए लागू किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इस अवधि में ट्रैफिक पर प्रभाव का अध्ययन कर स्थायी रूट चार्ट तैयार किया जाएगा।

प्रशासन ने कहा- ट्रायल फेज में लागू है प्रतिबंध- भोपाल ट्रैफिक पुलिस के अनुसार फिलहाल लिंक रोड नंबर एक, वीआईपी रोड, और बोट क्लब पर ई-रिक्शा के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। यह प्रतिबंध 23 जुलाई से एक सप्ताह के ट्रायल फेज के रूप में लागू किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस दौरान ट्रैफिक पर प्रभाव का आकलन किया जाएगा और आगे स्थायी रूट चार्ट तैयार किया जाएगा।

इससे पहले ट्रैफिक पुलिस यह साफ कर चुकी हैं कि ई-रिक्शा शुरू करने का उद्देश्य था कि वे कॉलोनियों से सिटी बस स्टॉप तक कनेक्टिविटी दें, लेकिन अब ये मुख्य मार्गों पर चलने लगे हैं, जिससे ट्रैफिक बाधित हो रहा है। उन्होंने बताया कि शासन ने ई-रिक्शा को परमिट की छूट दी हुई है, इसलिए उनके संचालन को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है।

प्रतिभाशाली बच्चों को श्रेष्ठ संस्थानों में प्रवेश के लिये नि:शुल्क कोचिंग व्यवस्था

भोपाल (नप्र)। स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश में प्रतिभाशाली बच्चों को देश के श्रेष्ठ संस्थानों में प्रवेश की कोचिंग के लिये सुपर 100 योजना संचालित कर रहा है। कोचिंग के लिये चयनित बच्चों को विभाग शासकीय सुभाष उच्च.मा.विद्यालय भोपाल और शासकीय मल्हार आश्रम उच्च.मा.विद्यालय इंदौर में निशुल्क कोचिंग के साथ आवासीय सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के अनेक बच्चों को देश के चयनित इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ और मैनेजमेंट से जुड़े कॉलेजों में प्रवेश मिला है।

स्कूलों में चयन प्रक्रिया- सुपर 100 योजना में मेघावी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये नि:शुल्क कोचिंग प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। इस योजना में प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों का परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाता है। इस वर्ष राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 26 जुलाई तक दिये जा सकते हैं। परीक्षा की तिथि 3 अगस्त 2025 रविवार को प्रथम पाली में जेईई के लिये और द्वितीय पाली में नीट की परीक्षा होगी।

परीक्षा केन्द्र प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में बनाये गये हैं। परीक्षा फार्म शुल्क 200 रूपये प्रति छात्र निर्धारित किये गये हैं। पिछले वर्ष इंदौर और भोपाल के सुभाष उच्च.मा.विद्यालय में करीब 300-300 विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग के साथ आवासीय सुविधा दिलाई गई थी।

निःशुल्क सुविधाएं

चयनित बच्चों को नि :शुल्क छात्रावास सुविधा, आधुनिक प्रयोगशाला, स्मार्ट एवं वर्चुअल क्लासेस और बच्चों को करियर काउंसलिंग की बेहतर व्यवस्था रहती है। सुपर 100 योजना के माध्यम से बच्चों को एम्स, आईआईटी के साथ देशभर के अनेक कॉलेजों में प्रवेश मिला है। लोक शिक्षण संचालनालय ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को चयन प्रतियोगी परीक्षा में अधिक से अधिक छात्र शामिल हो सकें, इसके लिये योजना की जानकारी दिये जाने के निर्देश दिये हैं। आवेदन पर किये जा सकते हैं।

लव जिहाद आरोपियों के परिजन पुलिस अफसरों के साथी

एनएचआरसी मेंबर प्रियंक कानूनगो बोले, जांच की दिशा अपराध के संरक्षकों की तरफ होना चाहिए

भोपाल (नप्र)। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने यह फोटो ट्वीट कर कहा कि आरोपियों के चाचा से पुलिस के संबंध हैं।

भोपाल के एक कॉलेज में हिन्दू छात्राओं को टारगेट कर रेप करने, धर्म परिवर्तन कराने और ड्रग्स की लत लगाने के मामले में हुई कार्रवाई के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भोपाल पुलिस पर सवाल उठाए हैं। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने ट्वीट कर कहा है कि दो दिन पहले जिस यास्मीन मछली और शावर को पुलिस में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है उसका चाचा सोहेल पुलिस के कई अफसरों का दोस्त है। इन अफसरों के भोपाल में रहते निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। इसलिए इन्हें हटाने की कार्यवाही के लिए लिखा जा रहा है। कानूनगो ने सोहेल के साथ कुछ अफसरों की फोटो भी एक्स पर अपलोड की हैं।

कानूनगो बोले: अपराध के संरक्षकों की तरफ हो जांच- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने आज एक्स पर किए ट्वीट में लिखा है कि भोपाल का आपराधिक ताना-बाना समझिए। स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाली हिंदू लड़कियों को टारगेट कर उनको पार्टियों के बहाने ड्रग्स की लत लगवाना, बलात्कार करके वीडियो बनाना, वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल कर सामूहिक यौन शोषण करना और फिर इस्लाम में धर्मांतरण का दबाव बनाकर जीवन भर के लिए सेक्स स्लेव बना कर रखना। कानूनगो ने लिखा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भोपाल में दो माह पहले हुई जांच की फाइंडिंग्स में हमने साफ साफ लिखा है कि पुलिस की जांच अपर्याप्त है। जांच की दिशा अपराध के संरक्षकों की तरफ होना चाहिए, इसलिए इस पूरे मामले में मुख्य सचिव और डीजीपी को पुनः जांच के लिए निर्देश दिए गए थे।

अफसरों पर कार्रवाई जरूरी- प्रियंक ने लिखा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सख्ती के बाद दो दिन पहले जिस यास्मीन मछली और शावर को पुलिस ने ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है, उन दोनों के फोन में कथित रूप से 20 से अधिक लड़कियों के पोर्न वीडियो मिले हैं।

पुलिसकर्मियों को मुखबिर और अपराधियों में अंतर समझ नहीं आ रहा

प्रियंक कानूनगो ने मीडिया से कहा कि एक जुलाई को एनएचआरसी ने लिखकर जानकारी दी थी और कहा था कि हमारे विटनेस ने बताया है कि फरहान के शारिक मछली से रिश्तों की जांच की जानी चाहिए। इसमें ड्रग्स की भूमिका भी बताई गई है। अब जांच की सही दिशा शुरू हुई है। कानूनगो ने कहा कि 20 लड़कियों के वीडियो मिले हैं जिनका यौन शोषण किया गया है। ड्रग्स दिए गए हैं।

सबसे गंभीर बात यह है कि ये जघन्य अपराधी पुलिस वालों के साथ मधुर रिश्ते रखते हैं। कुछ पुलिस वाले इन अपराधियों के साथ गंभीर किस्म की दोस्ती रखते हैं। यह ठीक नहीं हैं। इंटेलिजेंस यूनिट का काम होता है कि ऐसे अपराधियों के बारे में समाज को जानकारी दें। यह एमपी का इंटेलिजेंस का फेल्योर है कि मैदानी पुलिसकर्मियों को मुखबिर और अपराधियों में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे पुलिसकर्मी शहर में रहे, जांच में शामिल रहे तो जांच की दिशा बदल सकती है। इस बारे में राज्य सरकार को निर्देश देंगे कि जांच की पवित्रता को बनाए रखा जाए।

कानूनगो ने कहा कि राजनीतिक लोगों का अधिक लोगों से मिलना जुलना होता है।

संपादकीय

अब फर्जी दूतावास भी !

इस देश में फर्जी कंपनियां, फर्जी स्कूल, कॉलेज, फर्जी पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फर्जी ब्रांच भी सुनने में आई थी, लेकिन अब फर्जी दूतावास के संचालन से यह सवाल बहुत संजीदा हो गया है कि आखिर इस देश में किसी को कानून कायदे का कुछ डर है भी या नहीं? दूसरे, गुप्तचर और सुरक्षा एजेंसियां क्या सोती रहती हैं? और तीसरे, क्या इस देश में लोग इतने मूर्ख और अज्ञानी हैं कि किसी पर भी भरोसा कर धंधा चलवा देते हैं, कोई रिपोर्ट तक नहीं करता। उत्तर प्रदेश का ताजा मामला सचमुच बेहद चौंकाने वाला है। वहां एसटीएफ़ की नोएडा यूनिट ने ग़ाज़ियाबाद में एक व्यक्ति को फ़र्ज़ी दूतावास चलाने के आरोप में गिरफ़्तार किया है। अभियुक्त ख़ुद को वेस्टआर्कटिका, सबोरगा, पॉलविया और लोडोनिया जैसे तथाकथित देशों का राजदूत बताकर लोगों से संपर्क करता था। एसटीएफ़ के मुताबिक़ वह ख़ुद को वेस्टआर्कटिका, सबोरगा, पॉलविया, लोडोनिया और कुछ कथित देशों का राजदूत बताकर लोगों से संपर्क करता था। उसके पास से कई आपत्तिजनक सामग्री जिनमें फर्जी पासपोर्ट, पैनकार्ड, विभिन्न देशों की नकली मोहरें 44 लाख 70 हजार रू.नकद, फर्जी नंबर प्लेटें आदि बरामद हुई है। बरामद गाड़ियों पर डिप्लोमैटिक स्टाइल की फ़र्ज़ी नंबर प्लेट लगी हुई थीं, जिन्हें किसी अधिकृत एजेंसी से मंज़ूरी नहीं मिली थी। इस व्यक्ति का नाम हर्षवर्धन जैन बताया गया है। पुलिस के अनुसार इस व्यक्ति ने ग़ाज़ियाबाद के कवि नगर क्षेत्र में एक किराए का मकान लिया था, जहां से वह कथित रूप से फ़र्ज़ी दूतावास संचालित कर रहा था। वह लोगों को प्रभावित करने, उनसे ठगी के इरादे से मॉर्फ्ड की गईं फ़ोटोग्राफ़ का इस्तेमाल करता था। पूछताछ में उजागर हुआ कि वह विदेश में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर और शेल कंपनियों के ज़रिए हवाला रैकेट चलाकर लोगों से ठगी करता था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक़ 14 साल पहले भी उसे एक मामले में गिरफ़्तार किया गया था। जिस कथित वेस्ट आर्कटिका देश का वो ख़ुद को राजदूत बताता था, वह एककाल्पनिक देश है, जिसे 2001 में अमेरिका के एक पूर्व नौसेना अधिकारी ट्रैविस मैकहेनरी ने बनाया था। वेस्ट आर्कटिका वास्तव में पर्यावरण पर काम करने वाली एक एनजीओ है, जो मानद 'राजदूत' जैसे पद, 'नागरिकता' और उपाधियां भी बांटता है। उसे दुनिया के किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। कथित देश का सारा जमा खर्च डिजीटल और प्रतीकात्मक ही है। याद करें कि पिछले साल छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के छपोरा में एक एसबीआई की एक फर्जी शाखा पकड़ी गई थी। जिसमें नौकरी लगाने को लेकर ठगी की जाती थी। यह फर्जी ब्रांच किसी बैंक की तरह काम करती थी और उसमें लोगों ने खाते भी खुलवा लिए थे, बगैर यह जानें कि क्या बिना अनुमति के कोई बैंक इस तरह शाखा खोल सकती है। लोगों के भोलेपन और लापरवाही का बैंक चलाने वाले ठगों ने खूब फायदा उठाया। जब लोगों ने इस तथाकथित बैंक की शिकायत की तो पुलिस ने छापा मार कर ठगों को गिरफ्तार किया। यहां सवाल उठता है कि क्या इस देश में ठगों और बदमाशों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं है। फर्जी बाबाओं से लेकर फर्जी बहुओं तक सब धड़ल्ले से चल रहा है। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। सभी का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से पैसा बनाओ। अगर पैसा है तो सब कुछ है। इस फर्जीवाड़े के प्रति लोक जागृति भी बहुत कम है। लोग किसी के भी झांसे में आकर मूर्ख बनने और ठगने के लिए तैयार हैं। यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इन सब पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए।

आने वाले सौ साल सहकारिता के

नजरिया

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

लेखक राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में चेयर प्रोफेसर हैं।

संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि सहकारी समितियाँ ऐसे स्वैच्छिक आर्थिक संगठन होते हैं, जहाँ सदस्य मिलकर कोई कामकाज करते हैं, जिसमें आर्थिक नुक़सान या अस्थिरता का कुछ जोखिम भी हो सकता है, और उसके ज़रिए आय अर्जित करते हैं। ये संस्थाएँ न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक रूप से भी लोगों को सशक्त बनाती हैं। यह कार्य भारत में मद्धिम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की पहल से बने नए मंत्रालय व अमित शाह के नेतृत्व के कारण इसे बल मिला। लेकिन इसके आने वाले समय यह कहेंगे कि सहकारिता का नया इतिहास कुछ वर्षों में भारत ने तैयार किया और ऐतिहासिक सहकारिता-विश्वास भारतीय नागरिकों के बीच पैदा किया है। भारत में इस समय लगभग 8 लाख सहकारी संस्थाएँ हैं जिनके ज़रिए आर्थिक विकास और लोगों के सशक्तीकरण में सहयोग मिल रहा है, यह कोई मामूली बात नहीं है।

भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का मानना है कि अतीत आपने देखा, अब भविष्य की ओर देखो। पूरब से आने वाली सूरज की रश्मियाँ आपको ताजगी से भर देंगी। अब पूरब से आने वाली सूरज की रश्मियों में सहकारिता की ओज है। सहकारिता की ओज से हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में उजाला पसरने जा रहा है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का उत्साहवर्धन निश्चय ही सहकारिता से जुड़े समाज को ऊर्जा से भर देगा और जो सोये हैं अभी तक उन्हें जगाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। अमित शाह ने 'सहकार एवं रोजगार उत्सव' में युवाओं से कहा कि मोदी सरकार ने 11 साल के कार्यकाल में 60 करोड़ गरीबों के लिए घर, शौचालय, बिजली, गैस, पांच किलो मुफ्त अनाज और पांच लाख रुपए तक के इलाज और मुफ्त दवाइयों की व्यवस्था की। हर गांव, गरीब और किसान तक सहकारिता को पहुंचाने के लक्ष्य के साथ केन्द्र सरकार में एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया। आज 98 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता की सक्रिय भूमिका है। आगामी 100 साल सहकारिता के होंगे।

अतीत के सहकारिता के आन्दोलनों से अब तक के आंकलन के साथ गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय सहकारिता की पहुँच को रेखांकित किया कि देश के धान और गेहूं की खरीद में लगभग 20 प्रतिशत योगदान सहकारिता का है, जबकि 35 प्रतिशत उर्वरक और 30 प्रतिशत चीनी का उत्पादन सहकारिता के माध्यम से होता है। 20 प्रतिशत से ज्यादा उचित मूल्य की दुकानें–फेयर प्राइस शॉप भी सहकारिता के माध्यम से चलती हैं। 8 लाख 50 हजार सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 31 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हैं। यह जो करोड़ों भारतीयों का सहकारिता से जुड़ाव है, यह बहुत मायने रखता है। इसका बहुत ही महत्वा है कि चार वर्ष में ही भारत की इतनी बड़ी आबादी सहकारिता में अपनी उपस्थिति बना चुकी है। यह आगामी 100 बाद का जो उन्हें चित्र दिख रहा है, वह यूं ही नहीं है। यह उन्हें आभाष इसलिए हो रहा है क्योंकि सहकारिता भारतीय जीवन पद्धति, जीवन समृद्धि व उत्साहजनक भविष्य की कड़ी बनती जा रही है। उन्होंने खुद देखा कि विज्ञान व तकनीकी के साथ जैसे सहकारिता का जुड़ाव हो रहा है, युवा आबादी इसमें अपने भविष्य को संवारने का स्वप्न पाल रही है। वह अपने बुजुर्गों की विरासत में सम्मिलित सहकारिता को आगे बढ़ाना चाहती है।

एक बार प्राइमरी डेयरी को–ऑपरेटिव सोसाइटी–पीडीसीएस ऑनलाइन पंजीकरण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ हुआ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम अभियान के तहत सफलता की कहानियाँ जब सामने आयीं तो लोगों ने महसूस किया है कि सहकारिता भी सफलता की वजह बनती जा रही है। वन्दे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत सफलता की कहानियों ने यह बताया कि हमारी सहकारिता केवल कृषि व उद्यम तक सीमित नहीं है अपितु यह तो प्रकृति–जीवन–संस्कृति से जुड़ी हुई है। सहकारिता मंत्री ने अपने संबोधन में यह बार–बार रेखांकित किया है कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के चार वर्ष के भीतर हमने 61 पहलों के जरिये सहकारिता को मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि दो लाख नए पीएसीएस बनाने का काम शुरू हो गया है, इनमें से 40 हजार पैक्स बना लिए गए हैं। सभी पीएसीएस –पैक्स के कम्प्यूटरीकरण का काम पूरा कर लिया गया है और सभी राज्यों ने पैक्स के मॉडल बायलॉज़ स्वीकार कर लिए हैं। गोदाम भी बनाए जा रहे हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्ट और बीज संवर्धन के लिए नई सहकारी संस्थाएं बनाई गई हैं। यह भारत निर्माण के लिए उन युवाओं का दरअसल विश्वास जीतने का काम सहकारिता मंत्री ने किया है। इसके पहले की सरकारें सहकारिता को इतनी गंभीरता से देश के नागरिकों के बीच क्यों नहीं लायीं, यह बात समझ से परे की हैं। यदि यह कार्य व ऐसा कार्य जो सहकारिता मंत्रालय गठन के बाद विगत चार वर्षों में सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया है, ऐसा कार्य पिछले 75 वर्षों में किया गया होता तो, आज देश में सहकारिता की वजह से हमारे देश के किसान, मजदूर, श्रमिक व विभिन्न हितधारक भारत का भविष्य बदलने में सक्षम हो चुके होते, किसी अन्य सहयोग की अपेक्षा ही नहीं होती।

ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, नए अनुबंध–एमओयू, मानव संसाधन का निर्माण, नए रिसोर्सेज का चिन्हीकरण व उनको डिजिटल फॉर्म में सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया भी सहकारिता क्षेत्र में हो रही है। क्लाइमेट चेंज व सोशल जस्टिस जैसे विषयों को भी सहकारिता के समावेशी वैशिष्ट्य के साथ समाधान होगा। आत्मनिर्भरता व नवाचार से आर्थिक विकास की धारा जेंडर जस्टिस का कारण बनेंगी। भारत में सहकारी समितियों का जिस प्रकार बढ़ोतरी हो रही है, उनके उदासीनता को समाप्त करके इसे अभिरुचिजन्य बनाने की यदि कोशिश नया स्वरूप पाएगी तो भारत का 2047 तक विकसित राष्ट्र के पैमाने पर भारत 100 प्रतिशत खरा उतरेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सबसे अहम् बात यह है कि सहकारिता मंत्री का युवा मन युवा सहकारितासेवियों को जब तैयार कर लेगा, तो कोई लक्ष्य हमसे दूर नहीं होगा।

अपने युवा मानव संसाधन का बस तेजी से झुकाव सुनिश्चित करने में यदि भारत सरकार अभिरुचि दिखाएगी तो सब कुछ संभव सा होता दीखता है। सहकारिता मंत्री की ओर से की जा रही पहल के साथ जब वैश्विक स्तर पर इन्वेस्टमेंट करने वाली एजेंसीज सहकारिता से जुड़े लोगों व प्रतिष्ठानों के बीमा में अभिवृद्धि करेंगी और सुरक्षा की भावना से वे अभिरुचि दिखाकर आगे आने का प्रयत्न करेंगी तो निश्चय ही सहकारिता के 100 वर्ष किया 500 वर्ष भी स्वर्णिम काल में परिवर्तित हो सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट एजेंसीज की इच्छाशक्ति का अहम् योगदान है। वे ऐसा करेंगी तो आने वाले समय में विभिन्न चुनौतियों के बीच भी सहकारिता के कार्य आगे बढ़ेंगे।

संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि सहकारी समितियाँ ऐसे स्वैच्छिक आर्थिक संगठन होते हैं, जहाँ सदस्य मिलकर कोई कामकाज करते हैं, जिसमें आर्थिक नुक़सान या अस्थिरता का कुछ जोखिम भी हो सकता है, और उसके ज़रिए आय अर्जित करते हैं। ये संस्थाएँ न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक रूप से भी लोगों को सशक्त बनाती हैं। यह कार्य भारत में मद्धिम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की पहल से बने नए मंत्रालय व अमित शाह के नेतृत्व के कारण इसे बल मिला। लेकिन इसके आने वाले समय यह कहेंगे कि सहकारिता का नया इतिहास कुछ वर्षों में भारत ने तैयार किया और ऐतिहासिक सहकारिता–विश्वास भारतीय नागरिकों के बीच पैदा किया है। भारत में इस समय लगभग 8 लाख सहकारी संस्थाएँ हैं जिनके ज़रिए आर्थिक विकास और लोगों के सशक्तीकरण में सहयोग मिल रहा है, यह कोई मामूली बात नहीं है। जब देश में सहकारी संस्थाओं की संख्या 8 करोड़ हो जाएगी। जब देश में सहकारी संस्थाओं का पूर्णतया डिजटलीकरण हो जाएगा। जब देश में त्रिभुवन यूनीवर्सिटी जैसी सहकारिता यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़कर कम से कम 10 हो जाएगी। जब देश में सहकारिता अनुसंधान में सतत विकास हमें दिखेगा तो संपूर्ण विश्व में भारत का सहकारिता आन्दोलन अपने वैभवकाल की ओर गति पा लेगा। हमारे देश को एक ऐसे समय की प्रतीक्षा है। हमारे देश के सहकारिता मंत्री अमित शाह को भी ऐसे समय प्राप्त कर लेने का विश्वास है।

अब आवश्यकता इस बात की है कि उस विश्वास को पूरा भारत मजबूती से विश्वासपूर्वक अपना सहयोग प्रदान करे। क्योंकि इसमें किसी के निहित स्वार्थ नहीं हैं, अपितु इसमें पूरे भारत का भविष्य है।

बैंकों से विश्वास डगमगाने की वजहें

आर्थिकी

थॉमस फ्रैंको

लेखक 'ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन' के पूर्व महासचिव हैं।

बीती एक मई से 'भारतीय रिज़र्व बैंक' (आरबीआई) ने बैंकों को यह अनुमति दी है कि वे ग्राहकों से एटीएम (ऑटोमेटेड टेलर मशीन) की मुफ्त सीमा से अधिक लेन-देन पर ज़्यादा शुल्क वसूल कर सकें। अपने ही बैंक के एटीएम से 5 बार मुफ्त लेन-देन की अनुमति है, जिसमें वित्तीय (जैसे नकद निकासी) और गैर-वित्तीय (जैसे बैलेंस जांचना) दोनों शामिल हैं। अगर आप नकद निकालते हैं और उसके बाद मशीन पूछती है कि 'क्या आप अपना बैलेंस देखना चाहते हैं?' और आप 'हां' पर क्लिक करते हैं, तो यह एक अलग लेन-देन माना जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर आपने 3 बार नकद निकाला और हर बार बैलेंस देखा, तो कुल 6 लेन-देन हो गए–और 6वें से शुल्क लगने लगेगा। किसी अन्य बैंक के एटीएम से शहर में लेन-देन करने पर 3 मुफ्त लेन-देन ही मिलते हैं। शहर से बाहर करने पर 5 मुफ्त लेन-देन मिलते हैं।

पर क्या आम ग्राहक यह सब जानता है? पहले प्रति अतिरिक्त लेन-देन पर रू. 21 चार्ज होता था, अब एक मई से रू. 23 + 18 प्रतिशत 'जीएसटी' (वस्तु एवं सेवा कर), यानी कुल रू. 27.14 प्रति लेन-देन वसूला जा रहा है। भले ही आप सिर्फ रू. 100 निकालें, शुल्क वही रहेगा। शायद यह वृद्धि छोटी लगे, पर देश में औसतन प्रतिदिन 600 करोड़ एटीएम लेन-देन होते हैं–जिससे बैंकों को ज़बरदस्त मुनाफा हो रहा है। 2023 में बैंकों ने एटीएम शुल्कों से रू. 8,000 करोड़ कमाए।

जब एटीएम शुरू हुए थे तो बैंकों ने ग्राहकों को ज़बरन एटीएम कार्ड दिए, यह कहकर कि अब आप 24 घंटे बैंकिंग कर सकते हैं, कतारों में नहीं लगना पड़ेगा, किसी भी शहर से पैसा निकाल सकते हैं। यह भी कहा गया कि आप छोटी-छोटी रकम कई बार निकाल सकते हैं इसलिए ज़्यादा नकदी ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब जब जनता को इसकी आदत पड़ गई, बैंकों ने शुल्क वसूलना शुरू कर दिया – और यह शुल्क भविष्य में और बढ़ता जाएगा। वर्ष 2016 में हुई नोटबंदी

से बैंकों पर लोगों का विश्वास टूटने लगा था। इसने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बर्बाद कर दिया और आम लोगों को बहुत कष्ट झेलना पड़े, सिवाय नव-धनाढ्य वर्ग के। अब हर चीज़ पर शुल्क वसूले जा रहे हैं। वर्ष 2023 में बैंकों ने 'न्यूनतम औसत बैलेंस' नहीं रखने पर रू. 21,000 करोड़ वसूले। केवल 'भारतीय स्टेट बैंक' (एसबीआई) ने 2020 में यह शुल्क समाप्त किया, लेकिन उसी साल एसएमएस शुल्क के नाम पर रू. 6,000 करोड़ वसूले गए।

इसके अलावा बैंक 'नकद लेन-देन शुल्क,' 'लेन-देन शुल्क,' 'चेकबुक शुल्क,' 'ऋण खाता निरीक्षण शुल्क' आदि कई प्रकार के शुल्क वसूल रहे हैं – जिन पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक' आंखें मूंदे बैठा है। उसे गरीबों पर लगाए जाने वाले 'न्यूनतम बैलेंस शुल्क' पर रोक लगानी चाहिए थी। 'जन धन योजना' के 30 प्रतिशत खाते बंद हो चुके हैं। खाता बंद करने पर रू. 500 तक का शुल्क लिया जाता है।

बैंक पूरी तरह 'जमा पूँजी' (डिपॉजिट्स) पर निर्भर हैं। भारत में 80 प्रतिशत से अधिक जमा धन घरेलू जमाकर्ताओं से आते हैं। 'करंट अकाउंट' (चालू खाता) पर कोई ब्याज नहीं मिलता और 'बचत खातों' में 'न्यूनतम औसत बैलेंस' पर साधारण ब्याज मिलता है। चालू खाता और बचत खाता की जमा राशि बैंकों की कुल जमा पूँजी का 40 प्रतिशत है, और इन्हें बैंकों द्वारा कर्ज देने में इस्तेमाल किया जाता है–जिससे बैंक भारी मुनाफा कमाते हैं। 1990 के दशक तक ये सारे शुल्क नहीं होते थे–फिर भी बैंक मुनाफे में चलते थे।

वर्ष 1991 में 'अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष' (आईएमएफ) और 'विश्वबैंक' की शर्तों के तहत तथा 'नरसिंहम समिति' की सिफारिशों के बाद बैंकिंग व्यवस्था का उद्देश्य बदल गया। बैंकों पर कॉरपोरेट कंपनियों को सस्ते ब्याज पर भारी कर्ज देने का दबाव बढ़ा। 'विकास वित्तीय संस्थाएं' (डॅवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन्स) – जो लंबे समय के ऋण देने में माहिर थीं – को बदलकर वाणिज्यिक बैंक बना दिया गया, जैसे - 'आईसीआईसीआई बैंक,' 'एक्सिस बैंक,' 'एचडीएफसी बैंक।'

इन बैंकों को निजी हाथों में सौंप दिया गया और अब इनमें अधिकांश विदेशी निवेशक हिस्सेदार हैं। सरकारी बैंकों को लंबी अवधि के ऋण देने पड़े, जो बाद में 'एनपीए' ('नॉन परफार्मिंग एसेट्स'/ गैर-निष्पादित ऋण) बन गए। वर्ष 2016 में 'दीवालियापन और दिवालियापन संहिता' (इंसाल्वेंसी एण्ड बेंकरप्सी कोड) लाया गया और 'राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण' (एनसीएलटी) की स्थापना हुई। 'हेयरकट' के नाम पर 80 प्रतिशत तक बकाया राशि माफ की गई, जिससे बैंकों को भारी घाटा हुआ।

इस घाटे की भरपाई के लिए सेवा शुल्क लगाए गए, पर उनसे भी भरपाई नहीं हो सकी, इसलिए जमा पर ब्याज घटाया गया। 'एफडी' (फिक्स्ड डिपॉजिट) की ब्याज दरें 18त्न से गिरकर 6.5त्न हो गईं। बचत खातों में 5-6 प्रतिशत की जगह अब सिर्फ 2-2.5 प्रतिशत मिल रहा है। जबकि कॉरपोरेट्स को कम ब्याज पर लोन मिल रहा है, आम लोगों के लिए 'गृह ऋण,' 'एमएसएमई ऋण' और 'शिक्षा ऋण' की दरें अब भी 11-12 प्रतिशत हैं। सन् 2024 में 449 कॉरपोरेट कंपनियों को रू. 100 करोड़ से ऊपर के लोन 5 प्रतिशत से कम ब्याज पर मिले। 10,838 कॉरपोरेट्स को 10 प्रतिशत से कम ब्याज पर लोन मिले। इन 'गरीब' कॉरपोरेट्स की मदद के लिए, छोटे जमाकर्ताओं को कम ब्याज और अधिक शुल्क देकर दंडित किया जा रहा है – और 'आरबीआई' बस देख रहा है। सरकारी बैंकों के निदेशक मंडलों में अब 'वर्कमेन निदेशक' और 'गैर-वर्कमेन निदेशक' नहीं हैं – यानी निगरानी करने वाले लोग नहीं बचे। 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों' (एनबीएफसी) पर ब्याज दरों की सीमा को भी 'आरबीआई' ने हटा दिया है।

बचत का महत्व

वर्ष 2023 में भारत की 'घरेलू बचत दर' पिछले 50 वर्षों में सबसे कम रही। अब लोग बैंक की बजाय सोना और 'रीयल एस्टेट' को बेहतर निवेश विकल्प मान रहे हैं। 'आरबीआई' ने खुद की यह नीति भी लागू नहीं की कि किसी एक कॉरपोरेट को रू. 10,000 करोड़ से अधिक कर्ज बैंकों के समूह से नहीं दिया जाना चाहिए। देश की 90 प्रतिशत आबादी कर्ज में डूबी हुई है। साहूकार इनसे 100 प्रतिशत तक ब्याज वसूल रहे हैं।

ऋण-दरों में पारदर्शिता पूरी तरह नदारद है। टाटा समूह को 'एयर इंडिया' खरीदने के लिए रू. 10,000 करोड़ का ऋण सिर्फ 4 प्रतिशत ब्याज पर कैसे मिल गया? अडानी और अंबानी समूह को कितना ब्याज देना पड़ा – कोई नहीं जानता। ऐसे में 'आरबीआई' को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उसकी गतिविधियाँ और निष्क्रियता दोनों ही देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा रही हैं। अब जागने का समय है। (सप्रेस)

वक्ता और विद्वान एक तुलनात्मक अध्ययन

कटाक्ष

रमेशचंद्र शर्मा

लेखक व्यंग्यकार हैं।

जब दो व्यक्ति अथवा वस्तु मिलते जुलते लगते हों तो भ्रामक स्थिति बन ही जाती है। ठीक वैसे ही जैसे फिल्मों के जुड़वा भाईयों को लेकर बन जाती है। राजनीति के एक जैसे नामो वाले दलों को लेकर बन जाती है। घूंघट वाली दुल्हनों को लेकर बन जाती है। चुनाव के दिनों में दलों के घोषणापत्रों को लेकर बन जाती है।साधु संतों की उपाधियों को लेकर बन जाती है।समाजसेवी व्यक्तियों और संस्थाओं को लेकर बन जाती है। बावजूद इसके कि इनमें कई फंडामेंटल डिफरेंसेज होते है। मगर दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा ही लफड़ा तब हो जाता है जब लोग वक्ता और विद्वान को लेकर भ्रम में पड़ जाते हैं । समझ में नहीं आता है कि जो सामने हैं उनमें कौन वक्ता है और कौन विद्वान हैं।दोनों के दो हाथ,दो पांव,दो आंखे,दो कान एक नाक ,एक तोंद, एक गला। समझ में नहीं आता कि अंतर करें तो कैसे करें।दोनो एक जैसे चलते हैं। एक जैसे जैसे बोलते हैं।एक जैसे कुर्सी पर बैठते हैं।और तो और अपनी पत्नियों से भी एक जैसे डरते हैं। इसके बाद भी एक जैसे मौका लगने पर पड़ोसन से बतिया लेते हैं।

कभी - कभी तो वक्ता विद्वान और विद्वान वक्ता लगने लगता है। फिर भी अगर आपकी पकड़ मजबूत हो तो आप वक्ता और विद्वान के अंतर को पकड़ सकते हैं। इस बारे में हम सबसे पहले वक्ता को देखते है। वक्ता हर वक्त आत्मविश्वास से भरपूर दिखेगा जब आयोजक उसे उसको मंच की और रखी कुर्सी तक ले जाता है तो वह इतने आत्म विश्वास से कुर्सी पर बैठता है जैसे कुर्सी सहित ही जन्मा हो।अपना नाम पुकारा जाने पर वह माइक के पास आकर माइक को बड़ी हिकारत से देखता है।फिर श्रोताओं को इस तरह से देखता है जैसे किसान मक्के के खेत में खड़े होकर भुट्टो को देखता है। फिर गले में पड़ी माला को टेबल पर फेंकने के अंदाज में रखता है। मूल मुद्दे पर आने के पहले इधर उधर की बातें करने के बाद आयोजकों को धन्यवाद अदा करता है ।साथ ही यह भी कहना नहीं भूलता है कि वह बड़ी व्यस्तताओं में से बमुश्किल वक्त निकाल कर आया है। फिर वह कई गियर बदलने के बाद मूल विषय पर आता है।मगर रह रह कर उसकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है।जिसको वह अनदेखा कर देता है और भानुमती की तरह कही की ईंटें और कहीं के रोड़े जोड़ कर अपने वक्तृत्व कला का लोहा मनवा कर श्रोताओं की तरफ गर्व से देखता है।श्रोता और आयोजक चूंकि समझदार होते हैं अतः तालियां बजाकर खुद को धन्य करते हैं। माईक से हटते हुए वक्ता कहता है कि उसे अन्य प्रोग्राम में भी जाना है इसलिए समयाभाव के कारण वह रुक नहीं पाएगा।वह बड़ी ठसक से चल देता है।आयोजक उसका स्मृति चिन्ह,साल और मालाएं उठाकर उसे गेट तक छोड़ने जाते है।

चलिए साहेबान, अब बात करें विद्वान की।वह वक्ता की तरह घंटे भर लेट नहीं आता है बल्कि तभी आ जाता है जब आयोजक कुर्सियां लगा रहे होते है और संस्था का बैनर टांग रहे होते है।विद्वान इसमें भी सहज भाव से सहयोग करने लगता है। खैर,कार्यक्रम शुरू होता है। आयोजक उसे मंच की तरफ ले जाए इसके पहले वह खुद जाकर पहले श्रोताओं का अभिवादन करता है और कुर्सी पर सहमा हुआ सा बैठ जाता है। इस पर कुछ लोग उसे भयभीत तो कुछ विद्वत्ता के बोझ से दबा हुआ मानते हैं। दीप प्रज्वलन के दौरान भी वह पीछे जाकर खड़ा हो जाता है वह आयोजकों,नेताओं और वक्ता को ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करता है। स्वागत के दौर में वह माला पहन तो लेता है मगर तत्काल सामने रखी टेबल पर रख देता है। संबोधन के लिए जब उसका नाम पुकारा जाता है तो वह बोलने के पहले श्रोताओं को करबद्ध प्रणाम करता है। फिर आयोजकों को धन्यवाद अदा कर अपना संबोधन शुरू करता । इसके संबोधन के दौरान पता ही नहीं पड़ता है कि कब वह भाषण रूपी सरगम के आरोह पर आया और कब अवरोह पर चला गया।अपने भाषण के अंत में श्रोताओं सहित सबका धन्यवाद अदा कर अपनी जगह पर बैठ जाता है प्रोग्राम समाप्त होने पर सबके साथ श्रोताओं के बीच नाश्ता करता है। विदा होते वक्त अपना स्मृति चिन्ह,साल और श्रीफल खुद ही उठा कर अपने दुपहिए पर सवार होकर चला जाता है।

तो श्रीमानजी,आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपको वक्ता और विद्वान का अंतर बखूबी समझ में आ गया होगा। अब कभी कंफ्यूजन में मत पड़ना कि कौन वक्ता है और कौन विद्वान। फिर भी होता है तो आपको एक गूढ़ बात बता दूं कि वक्ता हर मंच पर बैठा हुआ मिल जाएगा और विद्वान यदाकदा ही मंचासीन दिखेगा।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

लोकतंत्र से भी जुड़े हैं सड़क और गड्ढे

व्यंग्य

डॉ. प्रेमचंद द्वितीय

लेखक व्यंग्यकार हैं।

हर साल जब भी बरसात आती है भले हीलोग किसी को कोसे न कोसे, गड्ढों को जरूर कोसते हैं और सड़क का रोना रोते हैं। लेकिन सड़क का मानना है कि मैं जब नहीं होऊंगी तब गड्ढों की भी कोई औकात नहीं रहेगी। आखिर गड्ढे कहां होंगे सड़क पर ही होंगे। यही नहीं सड़कों को लेकर जब बिहार में, विपक्ष, सड़क पर उतरा तो सड़क की कोख में पनपे गड्ढे बोल पड़े आज हमारी मुलाकात लोकतंत्र से हो गई।

यह समाचार सुनकर पंडित शिवनारायण जी मॉर्निंग वॉक में सड़क के गड्ढे में गिरते गिरते बचे और संभल कर बोले, अरे गड्ढों का सड़क से और सड़क का गड्ढों से चोली दामन का साथ तो है ही, वही सड़क और गड्ढे लोकतंत्र से भी जुड़े हैं। लोकतंत्र की सड़क पर इतने बड़े–बड़े गड्ढे हैं कि उन्हें भरने में हर सियासी दल को पसीना आता है। वे उन्हें भरने का नाटक खेलते हैं लेकिन गड्ढे ठहरे में फिर हो जाते हैं। कोई कोई तो इन गड्ढों को इतना भरते हैं कि वे टिबडडे में तब्दील हो जाते हैं और जब गड्ढे की जगह टिबडडे दिखते हैं तो लोग इन पर टिबडडे को हटाने का राग अलापने लग जाते हैं,जबकि टिबडडे ज्यादा हट जाते हैं तो गड्ढे फिर अस्तित्व में आ जाते हैं।

पंडित जी के गड्ढे टिबडडे पुराण को सुनकर सुनील भैया बोले आखिर गड्ढे कैसे पनपे, यह भी सोचने का विषय है ।जब सड़क नहीं थी तो लोगों ने सड़क बनाने का दबाव बनाया, जब सड़क बन गई और गड्ढे उसमें हो गए तो उन्हें भरने के लिए वाहन चालक से लेकर पैदल चलने वाले और अपनी फ्लॉप

नेतागिरी को जिंदा करने के लिए अनेक छूटभैया गड्ढों को कोसते हैं और गड्ढों को मुद्दा बनाते हैं।

इस पर छेदीलाल जी बोले आपने नहीं पढ़ा एक शहर में तो सड़कों पर हुए गड्ढों का पता लगाने के लिए इंजीनियरों की कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी जांच करेगी और प्रतिवेदन रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट आने के बाद गड्ढे सुधारे जाएंगे तब तक बरसात ही चली जाएगी।

इस पर स्वामी संघवी जी बोले जैसे ही बरसात आती है सड़क बनाने वाली एजेंसी सड़कों पर गड्ढे गिनती है, प्रशासन इन गड्ढों को देखता है, नेतागिरी गड्ढों को लेकर सक्रिय हो जाती है। ज्ञापन, चेतावनी, आंदोलन इन गड्ढों की मेहरबानी से शुरू हो जाती है ।यह सब देखकर सड़के हंसती है और दबे स्वर में बोलती है के विभाग ने मेरी उम्र तय की थी लेकिन मटेरियल के, रियल, न होने से मेरी भ्रूण हत्या हो गई। मुझ पर चेचक की तरह गड्ढे हो गए ।जब गड्ढे हुए तो लोकतंत्र शासन तंत्र की बांछे खिल गई, अधिकारी, ठेकेदार गड्ढों को गिन गिन कर उनका पैच वर्क का कागजों पर ही पैच लड़ाने की योजना बनाने लगे। नेता किस्म के लोग गड्ढे वाली सड़क से संसद, विधानसभा में पहुंचने का सपना देखने लगे ।इन सड़कों पर गड्ढों से गाड़ियां पंचर होने लगी,जिससे पंचर सुधारने की दुकान खुलने लगी, पंचर सुधरे इस समय में लोगों को नाश्ता पानी करने के लिए ढाबे खुल गए। पालिका के पास शहर की सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने के आवेदन थे वे गड्ढों के कारण स्पीड लेस हो गए।

गारंटी पीरियड में बनी सड़क पर पड़े गड्ढों को भरे तो कैसे भरे, विभाग ने भारी वाहनों के प्रतिबंध के बावजूद सड़क पर से गुजरने और वाहनों के दबाव के कारण सड़क पर गड्ढों को पनपने का कारण बताते हुए हर वर्ष की तरह उच्च अधिकारियों को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट में लिखा कि यदि गड्ढे न होते तो इन सड़कों को कौन पहचानता और बगैर सड़क के गड्ढों की भी कोई औकात और अस्तित्व नहीं होता है इसलिए जहां जहां सड़के हैं वहां गड्ढों के अस्तित्व की चुनौती नहीं दे सकते। इस प्रतिवेदन से ही हर साल सड़क और गड्ढों में पैच होता है लेकिन पैच वर्क नहीं होता है।

अंकुरण

सत्येन्द्र पाण्डेय

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

रंचना प्रधान- विस्थापन और भेदभाव से जूझकर बनाया व्यक्तित्व

कंधमाल में रहते हुए वे लोक कल्याण प्रतिष्ठान से परिचित थीं जो आदिवासी अंचलों में बच्चों के लिए स्छूल और छात्रावास का संचालन करता था। इसके संचालक जे.बी. बलिराजसिंह जब भी भुवनेश्वर आते तो रंचना जी से मिलते और प्रतिष्ठान में सक्रिय होने का अनुरोध करते। 2014 में उनका एक दुर्घटना में दुखद निधन हो गया और सारा कामकाज रुक गया। संस्था के जिम्मेवार लोगों के आग्रह पर उन्होंने संस्था की जिम्मेवारी ले ली और इसके माध्यम से बच्चों को शेल्टर उपलब्ध कराने, शिक्षा से जोड़ने और बाल श्रम तथा बाल विवाह आदि को रोकने के लिए शहरी क्षेत्रों में काम करना शुरू कर दिया। 2021 में नेशनल फाउंडेशन फॉर इन्डिया के अंकुरण कार्यक्रम से उनका संस्थागत जुड़ाव हुआ जिसके कारण उनकी संस्था में संस्थागत प्रक्रियाओं में बेहतरी आई, संवैधानिक मूल्यों, जेंडर, संचार, वित्तीय प्रबंधन आदि पर बेहतर समझ बनी है। आज रंचना प्रधान भुबनेश्वर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में बच्चों के अधिकारों पर काम करने वाली एक मजबूत नेतृत्वकर्ता साथी के रूप में सम्मान के साथ पहचानी जाती हैं। यही सम्मान उनको अपने परिवार और बस्ती में भी हासिल हुआ है।

उड़ीसा भारत का एक खुबसूरत प्रदेश है। पूरी, लिंगराज और कोणार्क के मंदिर। कलिंग का इतिहास और बेहद सुन्दर समुद्र तट। लेकिन सभी की नावों को किनारे जल्दी नहीं मिल जाते और सफलता के लिए लम्बा संघर्ष करना पड़ता है। कंधमाल जिला सांप्रदायिक हिंसा के चलते अक्सर ख़बरों में रहता है। कंधमाल जिले के जिला मुख्यालय फुलवानी से 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गाँव है दामकापा। बुनियादी सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित। आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य की कोई उल्लेखनीय सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन हम तो आज से चार दशक पहले की बात कर रहे हैं।

एक लगभग भूमिहीन किसान परिवार में दूसरी बेटी के रूप में पैदा हुई रंचना जी। परिवार में खेती इतनी कम थी कि गुजारे तक के लिए अनाज पैदा नहीं हो पाता था। गुजर-बसर के लिए बच्चे भी परिवार की मदद करते थे क्योंकि और कोई चारा नही था। प्राथमिक पढ़ाई गाँव से 3 किलोमीटर दूर वाले गाँव में हुई जहाँ वे पैदल ही जाया करती थीं। इस बीच परिवार बढ़ रहा था। कुल मिलाकर चार बहने और दो भाई। पिता ने खेती छोड़कर ठेकेदारी करना शुरू किया जिससे आमदनी थोड़ी बढ़ गई और उनका दाखिला राइकिया के मिशन स्कूल में करा दिया जहाँ होस्टल भी था।

इस स्कूल में पढाई का स्तर अच्छा था और वे नई दुनिया के बारे में नई-नई बातें सीख रही थीं। पढाई के अलावा अन्य गतिविधियों में भी उनकी दिलचस्पी और रुझान था। शिक्षकों ने भी प्रेरित किया। उन्हें वाद-विवाद प्रतियोगिता बहुत पसंद थी। जब वे हाई स्कूल में पढ़ रही थीं तभी इसी सिलसिले में एक बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वे दूसरी स्कूल गई और प्रथम पुरुस्कार भी जीत लिया। यहीं उनका परिचय एक और प्रतिभागी से हुआ जो आगे जाकर दोस्ती और फिर प्रेम में बदल गया। इस प्रेम ने उनकी जिन्दगी को ही बदल दिया। सुरेन्द्र प्रधान के साथ उनका सम्बन्ध दोनों परिवारों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। रंचना जी के पिता ने उन्हें बहुत रोका, आगे की मुश्किलों के लिए चेताया। माँ की भी शामत आई क्योंकि पिता की नजर में बेटी की परवरिश के लिए वे ही जिम्मेवार थीं। बहरहाल, रंचना ने तय किया कि पिता की बात मान लेंगी और अपने इस निर्णय को बताने के लिए सुरेन्द्र जी के पास गई लेकिन पिता के दोस्त ने उनको देख लिया और पिता के गुस्से से बचने के लिए वे सुरेन्द्र के साथ उनके घर चली गईं।

यहाँ से उनके जीवन का एक मुश्किल दौर शुरू होता है और ससुराल में होने वाला भेदभाव भी। दोनों का सम्बन्ध अंतरजातीय था और ससुराल में उसे मान्यता नहीं मिली।

यद्यपि सुरेन्द्र का परिवार आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखता था लेकिन फिर भी सामाजिक अनुक्रम में रंचना का परिवार उनसे पीछे का माना जाता था। इसलिए रसोई से लेकर कुंए तक भेदभाव की एक अनंत दास्तान शुरू हुई जिस पर विराम लगा उनका बेटा होने के बाद। जब रंचना के पिता आये और उन्हें अपने साथ घर ले आये। लौटकर छूटी हुई पढ़ाई फिर शुरू हुई। राउरकेला के महिला पोलिटेक्निक में दाखिला लिया और 'मॉडर्न ऑफिस मेनेजमेंट' में डिप्लोमा हासिल किया। पढाई के बाद वे वापिस सुरेन्द्र जी की माँ के बुलावे पर उनके गाँव पहुँच गई।

इसी समय कंधमाल में ईसाईयों के खिलाफ सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए। अधिकांश आदिवासियों के घर जला

दिए गए जो ईसाई पंथ में विश्वास रखते थे। रंचना के परिवार को भी इसका शिकार होना पड़ा और दो रातें जंगल में शरण लेकर बिताने के लिए बाध्य हुए। उसके बाद राहत शिविर में कुछ दिन बिताने के बाद जीवन को दोबारा शुरू करने के लिए भुवनेश्वर की राह पकड़ी। आज भी रंचना जब इस घटना को याद करती हैं तो आँखें नम हो जाती हैं। विस्थापन का दर्द वही समझ सकता है जिसने इसे झेला हो। भुबनेश्वर आकर एक श्रमिक बस्ती में शरण लेते हैं। सुरेन्द्र एक नौकरी करना शुरू कर देते हैं। रंचना की भी सरकारी नौकरी लगती है लेकिन बेटी को जन्म देने के दौर में वे बहुत बीमार पड़ जाती हैं और अंततः नौकरी छोड़नी पड़ती है।

वे जिस बस्ती में घर बनाते हैं, उसकी हालात बहुत ख़राब थी। बुनियादी नागरिक सुविधाएँ भी हासिल नहीं थीं। सड़क, नाली, पानी की दिक्कत तो थी ही, घर भी कच्चे थे और रहने लायक नहीं थे। अधिकतर बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और बालश्रम अथवा नशे की गिरफ्त में जा रहे थे। इन सब के लिए रंचना काम करना शुरू करती हैं। वे समझ गई थीं कि बदलाव का रास्ता शिक्षा से ही निकलेगा। इसी बीच एक घटना हो जाती है। बस्ती में एक परिवार में माता-पिता का निधन हो जाने से एक छोटा बच्चा शेष बचता है। रंचना इसके पालन-पोषण की जिम्मेवारी ले लेती हैं। फिर कोई और आकर तीन बच्चे इनके पास छोड़ जाता है और यह सिलसिला चलने लगता है। ये बच्चे दिन में स्कूल जाते और रात में रंचना जी के घर में भोजन करते और सोते। एक ऑटों कम्पनी के मालिक को जानकारी लगी तो उसने दो बोरी चावल हर महीने इन्हें देने का इंतजाम कर दिया।

कंधमाल में रहते हुए वे लोक कल्याण प्रतिष्ठान से परिचित थीं जो आदिवासी अंचलों में बच्चों के लिए स्छूल और छात्रावास का संचालन करता था। इसके संचालक जे.बी। बलिराजसिंह जब भी भुवनेश्वर आते तो रंचना जी से मिलते और प्रतिष्ठान में सक्रिय होने का अनुरोध करते। 2014 में उनका एक दुर्घटना में दुखद निधन हो गया और सारा कामकाज रुक गया।

संस्था के जिम्मेवार लोगों के आग्रह पर उन्होंने संस्था की जिम्मेवारी ले ली और इसके माध्यम से बच्चों को शेल्टर उपलब्ध कराने, शिक्षा से जोड़ने और बाल श्रम तथा बाल विवाह आदि को रोकने के लिए शहरी क्षेत्रों में काम करना शुरू कर दिया। 2021 में नेशनल फाउंडेशन फॉर इन्डिया के अंकुरण कार्यक्रम से उनका संस्थागत जुडाव हुआ जिसके कारण उनकी संस्था में संस्थागत प्रक्रियाओं में बेहतरी आई, संवैधानिक मूल्यों, जेंडर, संचार, वित्तीय प्रबंधन आदि पर बेहतर समझ बनी है। आज रंचना प्रधान भुबनेश्वर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में बच्चों के अधिकारों पर काम करने वाली एक मजबूत नेतृत्वकर्ता साथी के रूप में सम्मान के साथ पहचानी जाती हैं। यही सम्मान उनको अपने परिवार और बस्ती में भी हासिल हुआ है। उनकी प्रेरणा से सैकड़ों बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल हो सके हैं। अनेक बच्चों को बाल श्रम से निकाला जा सका है और बाल विवाह रोकने के लिए समाज को प्रेरित किया गया है। उनके नेतृत्व में लोक कल्याण प्रतिष्ठान एक गतिशील संस्था के रूप में अपनी ख्याति पुनः अर्जित कर पाई है। वे अपने लिए यही पुरुस्कार सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं।

पर्यावरण

अरूण कुमार डनायक

लेखक गांधी विचारों के अध्येता व समाजसेवी हैं।

प्रकृति के प्रहरी- अमेरिकी राष्ट्रीय उद्यानों का समर्पण

कैलिफोर्निया की सिएरा नेवादा पर्वतमाला की गोद में स्थित सेकोइया और किंग्स कैनियन राष्ट्रीय उद्यान, न केवल प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग हैं, बल्कि यह धरती पर जीवित विशालतम वृक्षों की प्रेरणादायक गाथा भी कहते हैं। एक-दूसरे के समीप बसे इन दोनों राष्ट्रीय उद्यानों की प्राकृतिक भव्यता, गगनचुंबी सिकोइया वृक्षों, शांत घाटियों और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों ने इन्हें वैश्विक मानचित्र पर अद्वितीय बना दिया है। सेकोइया नेशनल पार्क अपने घने जंगलों, फर्न, चीड़, देवदार और सबसे खास - विशालतम सिकोइया वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं किंग्स कैनियन राष्ट्रीय उद्यान गहरी घाटियों, शांत नदियों, और मन मोह लेने वाले झरनों जैसे मिस्ट फॉल्स, ग्रिज़ली फॉल्स और रोअरिंग रिवर फॉल्स के लिए जाना जाता है। पार्क में बहती हुई साउथ फोर्क किंग्स रिवर इस घाटी की जीवनरेखा है, जो अपने किनारों पर हरियाली, पक्षियों और जंगली जानवरों का आश्रय बनाती है।

सेकोइया पार्क का सबसे अद्भुत आकर्षण है 'जनरल शर्मन ट्री' - पृथ्वी का सबसे विशाल जीवित एकल वृक्ष। इसकी ऊँचाई लगभग 275 फीट है, तने का व्यास 36 फीट और अनुमानित आयु 2,300 से 2,700 वर्षों के बीच है। इसका वजन लगभग 1,910 टन आँका गया है, जो इसे जैविक दिग्गजों की श्रेणी में सबसे ऊपर रखता है। इसका नाम अमेरिकी गृहयुद्ध के प्रसिद्ध सेनापति शर्मन के सम्मान में 1879 में रखा गया।

दूसरी ओर, किंग्स कैनियन नेशनल पार्क में स्थित 'जनरल ग्रांट ट्री' भी कम प्रभावशाली नहीं है। 267 फीट ऊँचा और 28.9 फीट आधार व्यास वाला यह वृक्ष 1867 में अमेरिकी राष्ट्रपति और युद्धनायक यूलिसिस एस. ग्रांट के नाम पर नामित किया गया था। 1926 में इसे 'नेशन का क्रिसमस ट्री' घोषित किया गया। एक ऐसा सम्मान जो इसकी स्थायित्व, सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। यदि ये वृक्ष बोल पाते, तो शायद यह अमेरिकी ग्यूरह युद्ध, यूरोपीय प्रवासियों के आगमन और रेड इंडियनों के संघर्ष की गाथाएँ सुनाते जो इन वनों के सन्नाटे में गूंजती हैं। इन उद्यानों की विशेषता सिर्फ जीवित वृक्ष नहीं, बल्कि वे वृक्ष भी हैं जो गिरकर भी मानव रचनात्मकता और प्राकृतिक संतुलन के प्रतीक बन गए। थार्प्स लॉग, एक विशाल

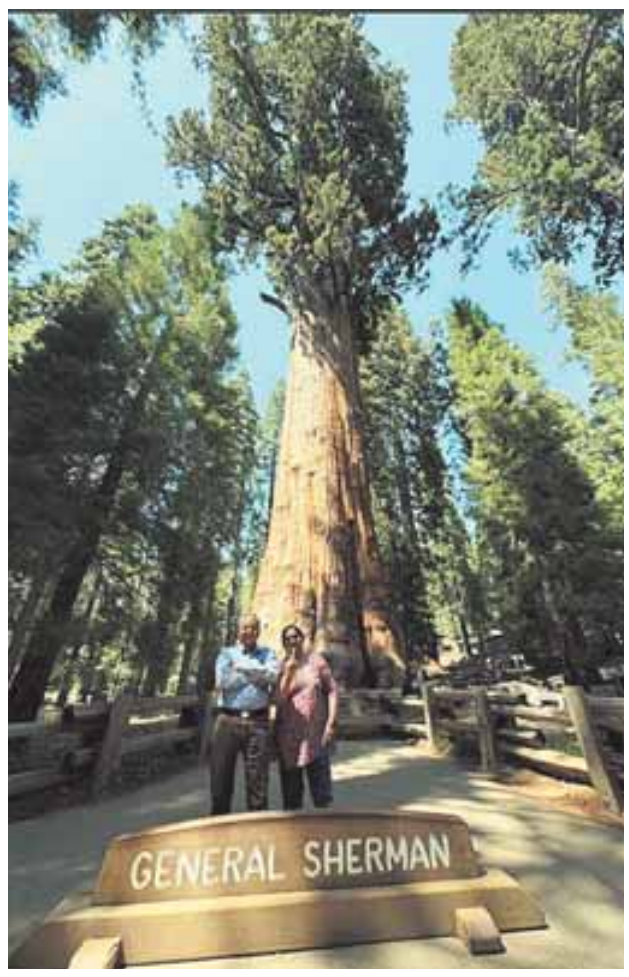

सेकोइया वृक्ष का खोखला हिस्सा है जिसे 1860 के दशक में हेलेन थार्प ने एक झोपड़ी में परिवर्तित कर दिया था।

टनल लॉग, एक और विशाल सेकोइया, 1937 में गिर गया था और बाद में उसमें एक सुरंग बनाई गई जिससे वाहन निकल सकते हैं। इसी तरह फॉलन मोनार्क, किंग्स कैनियन के ग्रांट ग्रोव में स्थित एक और विशाल वृक्ष है, जो गिरने के बाद अस्तबल और शरणस्थल के रूप में उपयोग किया गया। आज भी पर्यटक इसकी खोखली गुफा में पैदल चलते हुए भीतर का अनुभव कर सकते हैं। ये तीनों स्थल न केवल पेड़ों की विशालता और ताकत का परिचय कराते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि प्रकृति का हर रूप मानव के लिए अनुभव, आश्रय और सीख का स्रोत हो सकता है।

शताब्दी लट्ठे या सेंटरनियल स्टंप की कहानी भी प्रकृति और मानव की बदलती सोच को उजागर करती है। 1875 में एक 24 फीट व्यास वाला विशाल सेकोइया वृक्ष काटा गया और उसकी छाल को 1876 की फिलाडेल्फिया शताब्दी प्रदर्शनी के लिए भेजा गया। इस प्रदर्शन का उद्देश्य अमेरिका की 100वीं वर्षगांठ मनाना था। और इस वृक्ष को प्रदर्शित कर कैलिफोर्निया की प्राकृतिक भव्यता दिखाने का विचार किया गया। लेकिन परिवहन की कठिनाइयों के कारण केवल छाल को भेजा गया, जिसे पूर्वी अमेरिका के दर्शकों ने 'कैलिफोर्निया धोखा' कहकर संदेह की नजर से देखा। इस वृक्ष की कटाई में दो लकड़हारों को नौ दिन लगे, और इसके बचे हुए लट्ठे को स्थानीय महिलाओं ने बच्चों के रविवार स्कूल का मंच बना दिया। यह घटना उस समय की मानसिकता को दर्शाती है जब प्रकृति को केवल संसाधन के रूप में देखा जाता था। परंतु इसी सोच में बदलाव के कारण 1890 में सेकोइया नेशनल पार्क की स्थापना हुई, जिससे संरक्षण की एक नई चेतना का जन्म हुआ।आज, सेंटरनियल स्टंप एक ऐतिहासिक अवशेष के रूप में सिकोइया नेशनल पार्क में खड़ा है, जो मानव की महत्वाकांक्षा और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी के बीच संतुलन का सबक देता है। यह लट्ठा न केवल एक वृक्ष का अवशेष है, बल्कि एक ऐसी कहानी का प्रतीक है जो हमें प्रकृति के संरक्षण का महत्व सिखाती है। सेकोइया वृक्ष न केवल अपनी विशालता, बल्कि अपनी दीर्घायु और पर्यावरणीय अनुकूलन क्षमता के लिए भी जाने जाते हैं। इन वृक्षों की आयु 2,000 से 3,000 वर्ष तक हो सकती है। सिकोइया वृक्ष की शाखाएं बहुत नीचे से नहीं निकलतीं और आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, क्योंकि ये अधिकतर ऊँचाई वाले क्षेत्रों में उगते हैं, जहाँ सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है।

बर्फ की मोटी परत इनकी निचली शाखाओं को तोड़ सकती है, इसलिए पेड़ ने समय के साथ ऐसी शाखा संरचना विकसित की जो ऊपर केंद्रित होती है। इनकी छाल मोटी और रेशेदार होती है, जिसमें टैनिन अधिक होता है और रेजिन कम, जिससे ये जंगल की आग के प्रति अत्यंत प्रतिरोधी बनते हैं। इनकी जड़ें उथली होती हैं लेकिन दूर तक फैली होती हैं, जिससे इन्हें मजबूती मिलती है। आश्चर्यजनक रूप से, जंगल की आग इनके लिए एक संकट नहीं, बल्कि जीवन चक्र का हिस्सा होती है। आग की गर्मी से इनके शंकु खुलते हैं और बीज गिरते हैं। साथ ही, आग जंगल की सतह को साफ करती है जिससे बीजों को अंकुरण के लिए उपजाऊ स्थान मिलता है।

इन वृक्षों का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी उल्लेखनीय है। मूल अमेरिकी जनजातियाँ इन्हें धरती और आकाश को जोड़ने वाले पवित्र वृक्ष के रूप में मानती थीं। लोककथाओं में यह जंगल के रक्षक माने जाते थे, जो जीव-जंतुओं को प्राकृतिक आपदाओं से बचाते हैं। कैलिफोर्निया हाक्स से संबंधित एक लोककथा में कहा जाता है कि ये पक्षी सिकोइया के ऊँचे शिखरों पर घोंसले बनाते थे और इन्हें आत्माओं के दूत के रूप में देखा जाता था। कुछ कथाओं में सिकोइया को 'धरती के रक्षक' के रूप में देखा जाता था, जो जंगल की आग और प्राकृतिक आपदाओं से जीव-जंतुओं की रक्षा करते थे। हालाँकि सिकोइया वृक्षों में अद्वितीय जीवन शक्ति है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित जंगल की आग और मानवीय हस्तक्षेप ने इन पर संकट की छाया डाल दी है। सूखा, तापमान में वृद्धि, और तेज़ हवाओं ने इनके अंकुरण और जीवन पर प्रभाव डाला है। इसे देखते हुए नेशनल पार्क सर्विस और अन्य संस्थाएँ विभिन्न संरक्षण रणनीतियाँ अपना रही हैं। इनमें सबसे प्रमुख है नियंत्रित आग, जिसमें वन भूमि पर जानबूझ कर सीमित और नियंत्रित आग लगाई जाती है, ताकि सतह की झाड़ियों को हटाया जा सके और सिकोइया बीजों को उपजाऊ भूमि मिल सके। साथ ही, बीज एकत्र कर बीज बैंकों में संरक्षित किए जाते हैं, कृत्रिम रोपण किया जा रहा है, और ड्रोन व सैटेलाइट की मदद से वृक्षों की निगरानी की जा रही है।

सरकार इन राष्ट्रीय उद्यानों की सुरक्षा के लिए कड़े पर्यावरणीय कानून लागू करती है, पार्कों में अवैध कटाई और निर्माण पर रोक है, और स्थानीय स्तर पर संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अमेरिकी नागरिक भी सक्रिय भागीदारी करते हैं - वे स्वयंसेवक के रूप में पार्क की सफाई, वृक्षारोपण, आग पर नियंत्रण और पर्यटकों को जागरूक करने जैसे कार्यों में मदद करते हैं। अनेक नागरिक दान के माध्यम से संरक्षण कार्यक्रमों को आर्थिक सहयोग भी देते हैं।

भारतीय भी इन प्रयासों से प्रेरणा ले सकते है कि प्राकृतिक धरोहरों की रक्षा केवल सरकार का दायित्व नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। भारत में भी अनेक प्राचीन वनों और जैव विविधता वाले क्षेत्रों को संरक्षित करने हेतु आम जनता की भागीदारी आवश्यक है। शिक्षा, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और दीर्घकालिक संरक्षण दृष्टिकोण अपनाकर भारत भी अपने प्राकृतिक संसाधनों को सहेज सकता है। सिकोइया वृक्ष प्रकृति का एक चमत्कार हैं । ये वृक्ष हमें सिखाते हैं कि स्थायित्व केवल आकार में नहीं, संतुलन और समर्पण में है। इनकी छांव में खड़ा हर पर्यटक केवल इनकी भव्यता नहीं देखता, बल्कि प्रकृति से जुड़ने का गहरा अनुभव करता है। सिकोइया हमें याद दिलाते हैं कि संरक्षण कोई विकल्प नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व है।

अजित राय- वैश्विक सिनेमा की सैर कराने वाला गाइड चला गया

स्मृति शेष

विनोद नागर

(वरिष्ठ फ़िल्म समीक्षक एवं सिने अध्येता)

कल रात जब अचानक इंग्लैंड में भारत के यशस्वी फ़िल्म समीक्षक मित्र अजित राय के आकस्मिक निधन की सूचना मिली तो मन हक्का-बक्का रह गया। पता चला कि वे लंदन स्थित अपने घर में नींद के आग़ोश में सोते हुए ही अनंत यात्रा पर चले गये। आख़िर यायावरी उनके मिज़ाज का हिस्सा जो बन चुकी थी ।

चिकित्सकीय सलाह पर विगत कुछ वर्षों से मेरी कंप्यूटर, टीवी और मोबाइल स्क्रीन से दूरी बढ़ गई है। इसलिये सोशल मीडिया पर ताक-झाँक भी कम हो चली है। कल रात अनायास ही जब एक व्हॉट्स एप ग्रुप में मित्रवर श्रीराम तिवारी (जो इन दिनों मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार भी हैं) द्वारा साझा की गई दु:खद ख़बर 'अजित राय नहीं रहे' पढ़कर मन खिन्न हो गया। बाद में जब एमसीयू के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी से अपनी कॉमन फ्रेंडशिप के चलते अजित राय को लेकर लंबी बातचीत हुई, तो उनका गला भी भर आया।

दरअसल, जिस वक्त यह मनहूस ख़बर मिली तब मैं अगले दिन अपने सिने अध्येता साहित्यकार मित्र सुरेश पटवा की 'हिन्दी सिनेमा के कालजयी निर्माता-निर्देशक' पुस्तक के विमोचन समारोह में प्रस्तुत की जानेवाली पुस्तक समीक्षा को अंतिम रूप देने जा रहा था। किसे पता था कि अपने लिखित वक्तव्य की शुरुआत मुझे अजित राय जैसे सुधि फ़िल्म समीक्षक मित्र को श्रद्धांजलि देकर करनी पड़ेगी।

उम्र में मुझसे ग्यारह साल छोटे अजित राय से पहली मुलाक़ात दो-तीन साल पहले ही हुई थी। वे एमसीयू के तत्कालीन कुलपति के जी सुरेश के बुलावे पर भोपाल आये हुए थे। मैंने उन्हें अपने छह खण्डों वाले रचना समग्र की सिनेमा पर केंद्रित पुस्तकें- 'सिने झरोखा' और 'सिने सरोकार' भेंट करने के प्रयोजन से मिलने का सुविधाजनक समय और स्थान सूचित करने का अनुरोध किया।

मैं उनके संदेश की प्रतीक्षा करता रहा, पर कोई जवाब न आया। अगले दिन उन्होंने मुझसे घर का पता माँगा। मैंने पता और गूगल लोकेशन भेजा ही था कि थोड़ी ही देर में घर की कॉल बेल बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने अजीत राय मुस्कुराते हुए हाज़िर थे। वे करीब एक घंटा रुके और हमने सिनेमा पर ढेर सारी बातें कर अपनी पुस्तकों का आदान प्रदान किया।

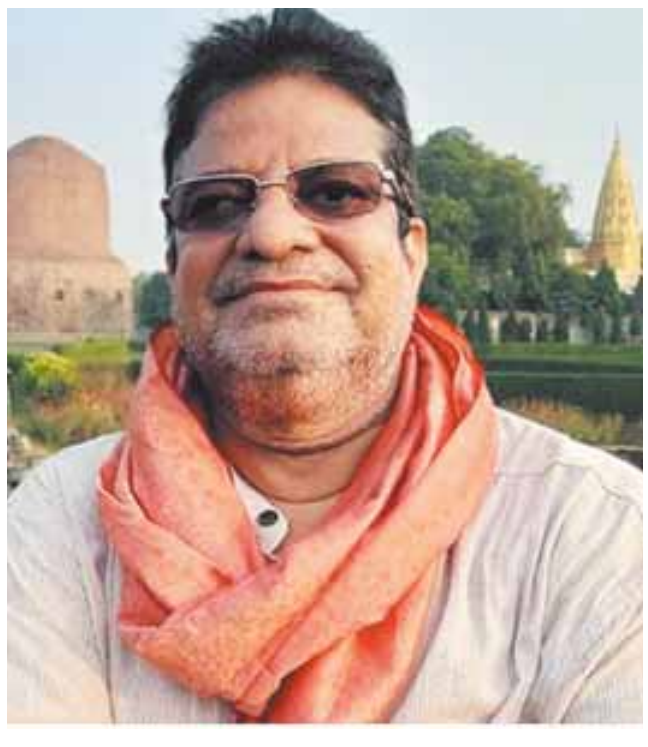

हमारी अगली मुलाक़ात पिछले साल दो सितंबर को भारत भवन में हुई। वे वहाँ बीवी कारंथ की स्मृति में आयोजित आदरांजलि समारोह में वक्तव्य देने आये थे। कार्यक्रम शुरू होने के पहले हम लोग भारत भवन के न्यासी सदस्य विजय मनोहर तिवारी आदि के साथ प्रेमशंकर शुक्ला के कक्ष में बैठकर बतियाते रहे। उस दिन कारंथजी की फ़िल्मों पर उनका वक्तव्य बेहद असरदार और रोचक था।

अभी दो तीन महीने पहले हमारी मुलाक़ात फिर एक चौंकाने वाले अंदाज़ में हुई। 21 अप्रैल को मैंने अपने दिवंगत पिताश्री की पंद्रहवीं पुण्य तिथि के अवसर पर उनकी आत्म कथा 'सबकी अपनी राम कहानी' का विमोचन कार्यक्रम भोपाल के विश्व संवाद केंद्र में रखा था।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव अशोक विजयवर्गीय, राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव और मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार श्रीराम तिवारी के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ ही था कि अतिथियों के स्वागत के दौरान अचानक हॉल में अजित राय प्रकट हुए। मेरी खुशी का पारावार न था। अग्रिम पंक्ति में विराजमान पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर, जानेमाने अभिनेता दंपति राजीव वर्मा और रीता वर्मा के अभिनंदन के साथ ही हमने डॉ. निरंजन श्रोत्रिय के हाथों से अजित राय का स्वागत बुके भेंट कर कराया।

इधर कोरोना काल में सहमें बॉलीवुड की कसक बयाँ करती मेरी अगली पुस्तक 'प्रजातंत्र में बातें फ़िल्मों की' की प्रस्तावना लिखने का अनुरोध मैंने उनसे किया था और पुस्तक की पांडुलिपि भी उन्हें भेज दी थी। मगर अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सवों में सम्मिलित होने की लगातार भागदौड़ के चलते यह अरमान अधूरा ही रह गया।

लंदन में रहते हुए भी उनका एक पैर भारत में टिका रहता था। 58 वर्षीय अजित राय से दिल्लगी करते हुए मैं उन्हें मज़ाक़ में एनआरआईएफ (नॉन रेसिडेंट इंडियन फ़िल्म क्रिटिक) कहता था। उन्हें फ़ोन करो तो ही पता लग पाता था कि जनाब फ़िलवक्त देस-परदेस में कहाँ हैं?

हाल के वर्षों में गले में लिपटा गमछेनुमा स्कार्फ़ उनकी वेशभूषा का अनिवार्य अंग बन गया था। आँखों में दृष्टि दोष के बावजूद सिनेमा को लेकर उनका दृष्टिकोण बिल्कुल साफ़ था। वाणी प्रकाशन से दो वर्ष पूर्व 2023 में छपकर आई 'बॉलीवुड की बुनियाद' उनकी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक रही है।

बहरहाल, अब जबकि अजित राय जैसा सुधि फ़िल्म समीक्षक नींद में चुपके से सबको अलविदा कह कर चला गया है, हम और हमारे सरीखे उनके असंख्य चाहने वाले बस ठगे से देखते रह गये हैं। उफ़्फ़..यादों में हमेशा बने रहेंगे अजित राय क्योंकि वैश्विक सिनेमा की सैर कराने वाला गाइड अब हमारे बीच नहीं रहा.. !

अवैध शराब बेचने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

बैतूल। अवैध शराब बेचने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 जून को अवैध शराब के परिवहन की सूचना मिलने पर मुलताई पुलिस टीम बिरूल रोड रवाना हुई, जहां कांजी हाउस के पास सामने से आ रही एक कार रुक गई, जिसे चालक लॉक कर अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। मौके पर कार के पास दो कागज के कार्टून पड़े मिले, जिनमें शराब होने की आशंका थी। जांच में कार की पिछली सीट व डिग्गी में कुल 22 कार्टून शराब के पाए गए थे, जिनमें 14 कार्टून देशी मदिरा प्लेन, 4 कार्टून ऑफिसर चॉइस व्हिस्की और 4 कार्टून गोवा व्हिस्की कुल 196 लीटर 56 मिली शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 1,10,220 पाई गई। शराब एवं वाहन को विधिवत जप्त कर कार्रवाई की विडियोग्राफी की गई। कार का चालक मिलिंद उर्फ मोंटी पिता राजेन्द्र पवार (37 वर्ष) निवासी सुभाष वार्ड मुलताई का कृत्य मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत अपराध पाया गया। प्रकरण में धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना के दिन से ही आरोपी फरार था। उसकी तलाश के लिए सतत प्रयास किए गए एवं मुखबिर लगाए गए थे। पुलिस द्वारा कई बार आरोपी के निवास स्थान पर दबिश दी गई एवं फरारी पंचनामा भी तैयार किया गया। पुलिस दबाव के चलते आरोपी ने 21 जुलाई को न्यायालय के समक्ष समर्पण कर दिया। जिसे पुलिस रिमांड पर लेकर विधि सम्मत कार्रवाई पश्चात पुनः न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक देवकरण डेहरिया, उनि छत्रपाल धुर्वे, सउनि श्रीराम मांडवी, आरक्षक अरविंद पटेल, आरक्षक सेवाराम एवं आरक्षक संजीत जाट की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

घर-घर भ्रमण कर मरीजों को देखा, पानी उबाल कर पीने और ताजा भोजन करने की दी समझाइश

बैतूल। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.मनोज कुमार हुरमाडे के निर्देश पर गुरुवार को जिला चिकित्सा दल के मेडिकल विशेषज्ञ डॉ.रोहित पराते एवं शिशु रोग चिकित्सक पीजीएमओ डॉ.सुरेंद्र कुमार कुशवाह द्वारा उल्टी दस्त प्रभावित ग्राम चिरमा टेकरी शाहपुर का घर-घर भ्रमण कर मरीजों को देखा गया एवं उपचार किया गया। घर-घर भ्रमण के दौरान उल्टी-दस्त के 4 मरीज मिले एवं अन्य सिरदर्द, हाथ पैर दर्द, खांसी-जुकाम के 20 मरीज मिले, जिन्हें उपचार दिया गया। 3 मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर में उपचार के लिए भर्ती किया गया। साथ ही चिकित्सा दल द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहपुर में पूर्व से भर्ती मरीजों को भी देखा गया, जो स्वस्थ हो चुके थे। कोई भी मरीज गंभीर स्थिति में नहीं पाया गया। स्वास्थ्य अमला मुख्यालय बनाकर मरीजों का उपचार कर रहा है। इसके अलावा ग्राम वासियों को पानी उबाल कर पीने, ताजा भोजन करने की समझाइश दी गई। वर्तमान में गांव की स्थिति नियंत्रण में है।

गाय को बचाने हाईवे पर पलटा तेल का टैंकर

बैतूल। बैतूल-नागपुर हाईवे पर गुरुवार दोपहर टायर फैक्ट्री के पास एक खाद्य तेल से भरा टैंकर पलट गया। हादसा उस वक्त हुआ जब चालक ने सामने अचानक आई गाय को बचाने के लिए स्टीयरिंग घुमा दिया। टैंकर के पलटते ही हाईवे पर तेल फैल गया, जिससे सड़क फिसलन भरी हो गई और कुछ देर के लिए यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। टैंकर चालक आदर्श पाल के अनुसार वह सतना से बैतूल स्थित ऑयल मिल की ओर जा रहा था। टायर फैक्ट्री के पास सामने अचानक गाय आ गई, जिसे बचाने के लिए स्टीयरिंग मोडऩा पड़ा, जिससे टैंकर असंतुलित होकर पलट गया। इसके बाद आसपास के ग्रामीण कुप्पियां और बर्तन लेकर तेल भरने के लिए पहुंच गए। टैंकर पलटने के बाद उसमें भरा खाद्य तेल सडक़ पर फैल गया। इससे सडक़ पर फिसलन बढ़ गई और वाहन चालकों की सुरक्षा को देखते हुए कुछ समय के लिए यातायात रोकना पड़ा। बैतूल बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। थाना प्रभारी अंजना धुर्वे ने बताया कि हादसे में कोई घायल या हताहत नहीं हुआ। हादसे की खबर फैलते ही आसपास के लोग कुप्पियां और बर्तन लेकर तेल भरने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन पुलिस ने तत्काल लोगों को वहां से हटाकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। पुलिस ने क्रेन की मदद से टैंकर को हटाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं, यातायात बहाल करने के लिए वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से गुजारा जा रहा है।

अनुसया सेवा संगठन ने किया ग्राम पांडरी में पौधा रोपण, ग्रामों में प्रारंभ हुआ शुभ कार्यों में वृक्षारोपण

बैतूल / मुलताई। प्रकृति को संस्कारों से जोडऩे एवं पौधों को जीवन के मूल्य में शामिल करने के लिए कार्य करने वाली अग्रणी संस्था अनुसया सेवा संगठन अब ग्राम ग्राम में अपना अभियान चला रहा है जिसमें युवाओं को अपने जीवन के महत्वपूर्ण दोनों को यादगार बनाने के लिए पौधारोपण करने के लिए प्रेरित कर रहा हैं। अनुसया सेवा संगठन के अध्यक्ष कृष्णा साहू ने बताया कि संगठन द्वारा गांव गांव में हर शुभ कार्यों पर वृक्षारोपण जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिससे ग्रामो में हर परिवार के लोग शुभ कार्य पर पौधे रोपित कर पालने का संकल्प ले रहे। इस तारतम्य में ग्राम पांडरी में अनुसया सेवा संगठन के सदस्यों द्वारा आकाश कवडक़र के जन्मदिन पर पौधों को रोपित कर जन्मदिन मनाया गया। साथ ही संगठन द्वारा सभी ग्राम वाशियो से ग्राम को हरियाली युक्त बनाने के लिए हर शुभ कार्यों पर वृक्षारोपण करने का आग्रह किया। इस अवसर पर ग्राम पांडरी के अनुसया सेवा संगठन के युवा आकाश कवडक़र चंद्रशेखर धाड़से राहुल कवडक़र अंशु कवडक़र आयुष प्रणव चढ़ोकार कमलेश धाड़से नितेश अनुराग प्रणव रोशन प्रदीप कवडक़र उपस्थित थे।

पुराने अस्पताल की भूमि पर लगेगा राखी बाजार

● बाजार में सभी सुविधा उपलब्ध कराएगी नगर पालिका ● जयस्तम से फवारा चौक मुख्य मार्ग पर नहीं लगेगी राखी की दुकानें

बैतूल / मुलताई। रक्षाबंधन पर्व पर प्रतिवर्ष अनुसार राखी व्यापारी जयस्तम चौक से फव्वारा चौक तक मुख्य मार्ग के फुटपाथ पर अपनी राखी की दुकान नहीं लगा पाएंगे। नगरपालिका सभी राखियों की दुकानों को एक साथ पुराने अस्पताल की भूमि पर लगाएगी और राखी बाजार में सभी आवश्यक सुविधा मुहैया कराएगी, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए जाएंगे। यह निर्णय मुलताई नगर पालिका परिसर सभाकक्ष में आयोजित एक बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा गडेकर, थाना प्रभारी देवेंद्र डेहरिया, तहसीलदार संजय बरइया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी वीरेंद्र तिवारी की उपस्थिति में लिया गया। पवित्र नगरी में एक सप्ताह से राखी बाजार को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, यही कारण है कि इस वर्ष ताप्ती तट पर अब तक राखी की दुकाने नहीं लगी है। नगर प्रशासन का तर्क था कि त्योहारों पर भारी भीड़ होती है, जिससे मुख्य मार्ग पर आवागमन की समस्या खड़ी हो जाती है, इसलिए नवाचार कर राखी की दुकानों को पुराने अस्पताल की रिक्त भूमि पर ले जाना आवश्यक है। जबकि परंपरागत रूप से ताप्ती तट पर राखी की दुकान लगाने वाले व्यापारी इसका विरोध कर रहे थे। राखी व्यापारियों का विरोध स्थान परिवर्तन के बजाय समय को लेकर था। व्यापारी का कहना था कि हम नए स्थान पर जाने का विरोध नहीं करते किंतु व्यापारी राखी की खरीदी दो महा पूर्व करता है अगर उन्हें स्थान परिवर्तन की जानकारी पहले दी होती तो वह कम खरीदी करते छोटे व्यापारी किसी तरह कर्जा लेकर खरीदी करते हैं स्थान परिवर्तन से उनका व्यापार प्रभावित होगा और उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए इस वर्ष नवाचार को विराम देकर यह व्यवस्था अगले साल की जाए।

राखी व्यापारियों को नहीं होने देंगे नुकसान .....

नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा गडेकर ने कहा कि राखी के व्यापारियों को नुकसान नहीं होगा। इस बात की गारंटी मेरी, मैं खुद फील्ड में खड़ी रहूंगी। अध्यक्ष ने राखी व्यापारियों को विश्वास दिलाया कि इस राखी बाजार का नगर पालिका प्रचार प्रसार करेगी। साथ ही इस बाजार में सभी व्यापारी एवं आने वाले खरीदारों के लिए समुचित व्यवस्था और सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। बैठक को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी देवेंद्र डेहरिया ने कहा कि नई जगह में व्यापारियों को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है किंतु व्यवस्था निर्माण की पहली जवाबदारी नगर वासियों की होती है। हम अधिकारी हैं आज है कल चले जाएंगे आपको यही रहना है और आज की गई व्यवस्था आपको कल भी लाभ पहुंचाएगी।

हम नहीं चाहते खुशी का त्योहार मातम में बदले .....

तहसीलदार संजय बरइया ने कहां कि शासन के स्पर्श निर्देश है हम राखी की दुकानों को दूसरे स्थान पर ले जाएंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी का त्योहार मातम में बदले, कोई दुर्घटना हो, मैंने देखा है मंदिर के सामने बहुत ट्रैफिक होता है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी वीरेंद्र तिवारी व्यापारियों से कहा कि पुराने अस्पताल की भूमि पर राखी दुकान एक साथ लगाने से सभी व्यापारियों को समान व्यापार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस बाजार का नगर पालिका प्रचार प्रसार करेगी। पुराने व्यापारियों को इस बाजार में प्राथमिकता दी जाएगी साथ ही पार्किंग के इंतजाम भी किए जाएंगे।

राखी के नए बाजार में क्या होगी व्यवस्था .....

पुराने अस्पताल की भूमि पर लगाए जाने वाले राखी के बाजार में कुल 60 दुकान आवंटित की जाएगी। प्लाट आवंटन में व्यापारियों के साथ पक्षपात न हो, इसके लिए चीट निकालकर दुकान आवंटित होगी। पुराने व्यापारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। नगर पालिका चलित शौचालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करेगी। राखी बाजार में सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम होंगे।

नशा एक ऐसा जहर है, जो व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देता है: संभागायुक्त

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में स्कूली बच्चों को नशे से दूर रहने का संदेश

बैतूल। मध्यप्रदेश पुलिस विभाग द्वारा प्रदेशव्यापी स्तर पर चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत बैतूल जिले के आमला स्थित पीएमश्री केवी एयरफोर्स स्टेशन स्कूल में गुरुवार को एक भव्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में नर्मदापुरम संभागायुक्त केजी तिवारी, पुलिस महानिरीक्षक मिथलेश कुमार शुक्ला, डीआईजी प्रशांत खरे, कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया, एयरफोर्स अधिकारी आर. के. रेड्डी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी, एसडीएम शैलेन्द्र बडोनिया, एसडीओपी मुलताई एसपी सिंह एवं थाना प्रभारी अमला सत्यप्रकाश सक्सेना सहित पुलिस एवं प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विद्यालय प्राचार्य मदन मोहन कटियार ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। नशे से दूरी, है जरूरी अंतर्गत सभी अधिकारियों ने हस्ताक्षर कर जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक श्री मिथलेश कुमार शुक्ल ने सभी को नशा न करने और नशे के प्रति जागरूकता फैलाने की शपथ दिलाई।

संभागायुक्त ने बच्चों को दिए सफलता के सूत्र .....

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संभागायुक्त श्री तिवारी ने बच्चों को नशे से दूर रहकर अपने जीवन के लक्ष्यों पर केंद्रित रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कई बार हम अपने जीवन में सही दिशा और अच्छी स्थिति में होने के बावजूद गलत आदतों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। नशा ऐसी ही एक बुरी प्रवृत्ति है, जो हमारे स्वास्थ्य, परिवार और समाज को धीरे-धीरे खोखला कर देती है। उन्होंने विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए फोर-पी प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस तथा फाइव-डी ड्रीम, डिजायर, डिसिप्लिन, डेडीकेशन और डिटरमिनेशन फार्मूलों को अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने बच्चों को आने वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवा पीढ़ी ही देश का भविष्य है और उनका सजग होना समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है।

आईजी ने नशे की रोकथाम के लिए किया प्रेरित .....

आईजी मिथलेश कुमार शुक्ला ने कहा कि नशा केवल उस व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और यहां तक कि देश को भी प्रभावित करता है। उन्होंने बताया कि मप्र पुलिस द्वारा प्रदेशभर में रैली, नुक्कड़ नाटक, स्कूलों में संवाद कार्यक्रम, चित्रकला प्रतियोगिताएं आदि के माध्यम से नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों के माध्यम से यदि नशे की रोकथाम का संदेश जाता है तो उसका प्रभाव और अधिक व्यापक होता है। बच्चे जब अपने घर या मोहल्ले में किसी को नशा करते हुए रोकते हैं, तो वह व्यक्ति उस पर विशेष ध्यान देता है।

नशे की लत व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को करती प्रभावित-डीआईजी

डीआईजी प्रशांत खरे ने कहा कि मप्र सहित पूरे देश में बड़ी संख्या में युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना के निर्देशन में पूरे प्रदेश में युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए मप्र पुलिस द्वारा 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशे से दूरी है जरूरी विशेष पखवाड़ा चलाया जा रहा है। यह अभियान जिले में सक्रिय रूप से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशे की लत व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को तो प्रभावित करती ही है, साथ ही वह समाज पर बोझ बन जाता है। उन्होंने युवाओं को जागरूक रहने, दूसरों को भी प्रेरित करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का आह्वान किया। विद्यालय प्राचार्य मदन मोहन कटियार ने अपने उद्बोधन में नशे के खिलाफ जनजागरण के लिए पुलिस विभाग बैतूल के प्रयासों की सराहना की और कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम छात्रों के मनोबल को मजबूत करते हैं और उन्हें सही दिशा में प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम के दौरान कक्षा 9वीं की छात्राओं पायल तायवाड़े, सुहाना सिंह और कीर्ति ने भी मंच से अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि नशा एक ऐसा धीमा जहर है, जो व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देता है। इससे न केवल उसका जीवन बर्बाद होता है, बल्कि पूरा परिवार, समाज और देश प्रभावित होता है। छात्राओं ने कहा कि नशे से दूर रहना ही समाधान नहीं है, बल्कि नशे की गिरफ्त में आए व्यक्तियों का सहारा बनना और उन्हें सही मार्ग दिखाना भी उतना ही आवश्यक है।

नवांकुर सखी कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव पहल : प्रिया चौधरी

मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद आठनेर ने किया नवांकुर सखी हरियाली यात्रा का भव्य आयोजन

बैतूल। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा नवांकुर सखी हरियाली यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ हरियाली अमावस्या से पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड आठनेर के निर्देशन में संबद्ध लीड नवांकुर संस्था नगर विकास प्रस्फुटन समिति के द्वारा सेक्टर के ग्राम धामोरी के दुर्गा मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया।कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों के द्वारा मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पौधों के पूजा अर्चना के साथ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम के उपसरपंच मारुति वाडेकर द्वारा की गई। कार्यक्रम की रूपरेखा विकासखंड समन्वयक आठनेर मधु चौहान द्वारा प्रस्तुत की गई। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद की जिला समन्वयक प्रिया चौधरी ने कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि पर्यावरण संरक्षण एवं जनजागरूकता के उद्देश्य से नवांकुर सखी हरियाली यात्रा का आयोजन पूरे प्रदेश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष (राज्य मंत्री) पर्यावरणविद मोहन नागर के प्रभावी मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इसके अंतर्गत नवांकुर सखियां 11 बीज रोपित एवं अंकुरित पौधे रोपित थैलियों के माध्यम से अपने घर की बगिया में पौधे विकसित करेंगी। मप्र जन अभियान परिषद की इस नवाचारी पहल से प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में 5500 पौधे तैयार होंगे।अभियान के तहत प्रदेश में 1 लाख 56 हजार 500 नवांकुर सखियों द्वारा 17 लाख 21 हजार 500 पौधे तैयार किए जाएंगे। कार्यक्रम के अध्यक्ष मारुति वाडेकर ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह हरियाली यात्रा आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और हरित भविष्य देने की दिशा में एक मजबूत कदम सिद्ध होगी। नवांकुर सखी कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अभिनव पहल है। मंचीय कार्यक्रम के पश्चात हरियाली यात्रा का शुभारंभ ग्राम के दुर्गा मंदिर से नवांकुर सखियों द्वारा हाथों में पौधे,पर्यावरण संरक्षण से जुड़े स्लोगन पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ और हरियाली है तो खुशहाली है के नारों के साथ किया गया।

नवांकुर संस्था ने बांसपानी में महिलाओं को वितरित किए 700 आम के पौधे

हरियाली अमावस्या पर महिलाओं ने लिया हरियाली का संकल्प

बैतूल। ब्लाक बैतूल के ग्राम बांसपानी में हरियाली अमावस्या के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वावधान में चल रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत नवांकुर सखी हरियाली यात्रा संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में गांव की स्व-सहायता समूह की महिलाओं को विशेष रूप से शामिल किया गया। सुबह पंचायत भवन में एकत्रित हुई महिलाओं और शासकीय प्राथमिक शाला की छात्राओं ने वहां से विजासनी देवी मंदिर तक कलश यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान महिलाएं भजन-कीर्तन करते हुए मंदिर तक पहुंचीं। पूजा-अर्चना के पश्चात पुनः पंचायत भवन लौटीं। यहां नवांकुर संस्था के सचिव शैलेन्द्र मालवीय ने उपस्थित महिलाओं को 700 आम के पौधे वितरित किए। उन्होंने बताया कि पौधों की खरीद के बजाय गांव में ही नर्सरी बनाकर पौधे तैयार किए गए हैं, जिससे लागत भी कम आई और स्थानीय महिलाओं को काम भी मिला। पौधे तैयार करने में ग्राम की महिलाओं का विशेष योगदान रहा।पौधे प्राप्त कर सभी महिलाओं ने उन्हें लगाने और उनकी देखरेख करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। इस अवसर पर शा. प्रा. शाला के प्रधान पाठक नंदकिशोर धुर्वे, संस्था के सचिव फगन ऊईके, सहायक सचिव रामपाल बामने, पूर्व उपसरपंच मोहन जौंजारे, ज्योति स्व-सहायता समूह अध्यक्ष श्रीमती चित्रलेखा जौजारे, दुर्गा स्व-सहायता समूह अध्यक्ष सुखमनी भलाबी, पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती दुर्गा जौजारे, पूर्व सरपंच बीरबती यादव, गीता यादव, अम्बा उबनारे, शांति इवने, मीरा जौंजारे सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम ने गांव में हरियाली के प्रति नई चेतना जागृत की और ग्रामीणों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न किया।

चयनित काउंसलर और विषय विशेषज्ञों की टीम ने दिया कैरियर मार्गदर्शन

सुबह सवेरे संवाददाता। शासन के निर्देशानुसार जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा चयनित काउंसलर और विषय विशेषज्ञों की टीम के माध्यम से विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिले के शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों मे अध्ययनरत छात्र /छात्राओं हेतु सत्र 2025 की शुरुआत से ही छात्र छात्राओं को कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करने एवं छात्र एवं छात्राओं के भविष्य निर्माण मे सहयोग के लिए कैरियर एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन की शुरुआत कर दी गई है ।

इसी क्रम मे जिला रोजगार कार्यालय इंदौर के उप संचालक रोजगार पी एस मंडलोई के मार्गदर्शन मे काउन्सलर एवं विषय विशेषज्ञों और मोटिवेशनल स्पीकर की टीम बनाकर जो विशेषकर शासकीय स्कूलों के छात्र छात्राओं

को बेहतर विषय चुनने में मदद कर सके इस हेतु शासकीय कस्तूरबा कन्या उ मा विद्यालय इन्दौर, शा उ मा विद्यालय बानगंगा इन्दौर ,शासकीय उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल इन्दौर के छात्र/छात्राओं को मार्गदर्शन देने हेतु भेजा गया । काउंसलर डॉ धीरज हसीजा, प्रियंका तिवारी एवं विषय विशेषज्ञ सीमा मिश्रा, विजेंद्र सोगानी ने करियर काउंसिलिंग एवम् भविष्य की केरियर योजनाओं के बारे में जानकारी दी द्य इन सभी ने मार्गदर्शन/वार्ता के माध्यम से शासन की स्वरोजगार और केरियर योजनाओं से भी अवगत कराया गया साथ ही बेहतर विषय चुनने एवं भविष्य की केरियर योजनाएं बनाने मे मदद मिले इस प्रकार की जानकारियां दी गईं। रोजगार कार्यालय के काउंसलिंग समन्वयक पवन गोयल ने आभार व्यक्त किया ।

धार की समाजसेविका नीलम पगारिया जैन बनी जैन राष्ट्रीय एकता संगठन मध्यप्रदेश महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष

नियुक्ति पर शुभचिंतकों ने दी बधाई

धार। जैन राष्ट्रीय एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक संजय शाह अहमदाबाद ने जेआरइएस मध्यप्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष (संस्थापक) समाजसेवी नीलेशकुमार सुराणा की अनुशंसा पर धार की समाजसेविका नीलम पगारिया जैन को जैन राष्ट्रीय एकता संगठन महिला विंग की मध्यप्रदेश इकाई की प्रदेश अध्यक्ष (संस्थापक) मनोनीत किया है। कार्यकाल चार वर्ष का रहेगा।

नियुक्ति पर नीलम पगारिया ने राष्ट्रीय अध्यक्ष शाह एवं प्रदेश अध्यक्ष सुराणा सहित सभी साथियों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि वह संगठन को विश्वास दिलाते है कि वह अपने कार्यकाल में संगठन विस्तार करेंगे एवं संगठन की सभी गतिविधियों

को अपने प्रदेश में लागू करेंगे एवं अपनी टीम के साथ राष्ट्रसेवा एवं जिनशासन की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभायेंगे।

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संस्थापक नीलेशकुमार सुराणा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में जिस तरह से मातृशक्ति को सम्मान दे रहे वह अत्यंत सुखद है एवं प्रशंसनीय है। हम भी अपने प्रदेश में संगठन के लिए महिला विंग का अलग से गठन करना चाह रहे थे एवं मातृशक्ति को बराबरी से आगे लाना चाह रहे थे ।हमें हमारे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय शाह की स्वीकृति मिली हम उनकी बहुत अनुमोदना करते है।

प्रदेश अध्यक्ष सुराणा ने आगे कहा कि महिला विंग के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और जहां जहां हम भाईयों का उन्हें साथ लगेगा हम हमेशा साथ खड़े मिलेंगे। अपनी नियुक्ति के बाद जैन राष्ट्रीय एकता संगठन महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष संस्थापक नीलम पगारिया ने कहा कि वह जल्द से जल्द संगठन की प्रदेश कार्यकारणी बनाकर पूरे प्रदेश में प्रवास करके तहसील एवं मंडल स्तर तक जाकर संगठन की टीम बनाएगी ।

यह जानकारी समाजसेवी राजेश नाहर ने दी।

सिंगरौली से एयरलिफ्ट कर लाए गए मरीज को एम्स भोपाल में मिला जीवन रक्षक इलाज

भोपाल। कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के नेतृत्व में एम्स भोपाल स्वास्थ्य सेवा, आपातकालीन चिकित्सा और गहन चिकित्सा उपचार के क्षेत्र में उत्कृष्टता की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। इसी क्रम में 23 जुलाई 2025 को नेहरू शताब्दी चिकित्सालय, सिंगरौली से एक अत्यंत गंभीर अवस्था में मरीज को एयरलिफ्ट कर एम्स भोपाल लाया गया। मरीज को दाहिने पैर में सेलुलाइटिस, सेप्सिस, सेप्टिक शॉक और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन की समस्या थी। सिंगरौली में स्थिति अत्यधिक गंभीर होने के कारण उसे उन्नत चिकित्सा सुविधाओं और जीवन रक्षक देखभाल की आवश्यकता थी। मरीज के एम्स भोपाल पहुंचते ही उसे तुरंत आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने तत्काल उपचार आरंभ किया। एम्स भोपाल की गहन चिकित्सा इकाई में सतत निगरानी और विशेषज्ञ उपचार के परिणामस्वरूप मरीज की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और अब वह स्थिर एवं बेहतर स्वास्थ्य स्थिति में है। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने कहा,एम्स भोपाल न केवल मध्यप्रदेश बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए एक भरोसेमंद जीवन रक्षक संस्थान बनकर उभरा है। दूरस्थ क्षेत्र से गंभीर स्थिति में आए मरीज को समय पर गहन उपचार देना हमारे डॉक्टरों, नर्सिंग और तकनीकी स्टाफ की प्रतिबद्धता और दक्षता को दर्शाता है। हमारा उद्देश्य हर मरीज को सर्वोत्तम इलाज और मानवीय देखभाल देना है।

वन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, गिरफ्तार

बालाघाट (नप्र)। बालाघाट में वनविभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में भरवेली पुलिस ने गुरुवार को फरार आरोपी रूपेश ब्रम्हें को गिरफ्तार किया है। यह इस मामले में तीसरी गिरफ्तारी है।भरवेली थाना प्रभारी संजय ऋषिश्वर ने बताया कि आरोपी रूपेश ब्रम्हें वनविभाग में नौकरी के नाम पर मुरैना के केमरा निवासी रामकुमार गुर्जर के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने में शामिल था। इससे पहले मुख्य आरोपी सुमित ब्रम्हें और फोटोकॉपी संचालक लक्ष्मीनारायण सहारे को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने रूपेश की गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में और भी लोगों के बारे में जांच जारी है और आगे भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।मामले के अनुसार, सुमित ब्रम्हें ने अपने साथियों के साथ मिलकर रामकुमार से वनविभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 30 हजार रुपए नगद और विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से 1 लाख 60 हजार रुपए लिए थे। आरोपियों ने रामकुमार को नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर, वनविभाग की वर्दी और आईडी भी दी थी।जब रामकुमार को आरोपियों पर शक हुआ, तो उसने भरवेली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को गिरफ्तार किए गए रूपेश ब्रम्हें को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है।

समाज को नशा और अपराध मुक्त बनाने के लिए प्रदेश पुलिस चला रही है जागरुकता अभियान

30 जुलाई तक जारी रहेगा अभियान,अभियान समाज और पुलिस की सहभागिता का सशक्त प्रयास

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि 'नशे से दूरी है जरूरी' अभियान केवल अभियान नहीं, मादक पदार्थों की लत से युवाओं को बचाने की दिशा में समाज और पुलिस की सहभागिता का सशक्त प्रयास है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित वृहद जन-जागरूकता अभियान 'नशे से दूरी-है जरूरी' के अंतर्गत भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में यह अभियान 15 से 30 जुलाई 2025 तक प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस मुख्यालय के नारकोटिक्स विंग द्वारा संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य किशोरों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना, उन्हें इस लत से दूर रखना और जो लोग पहले से नशे की गिरफ्त में हैं, उन्हें उचित परामर्श और सहयोग प्रदान कर पुनर्वास की दिशा में मार्गदर्शन देना है।

पुलिस के नशा मुक्ति अभियान से जुड़ीं स्वयंसेवी संस्थाएं-नशा मुक्ति अभियान में प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस अधिकारी, नगर एवं ग्राम रक्षा समितियां और कम्युनिटी पुलिसिंग के सभी विंग साथ मिलकर स्कूल, कॉलेज के युवाओं और आमजनों को नशे से दूरी बनाने के लिए जागरुक करेंगी। स्वयंसेवी संस्थाओं को भी प्रदेश स्तरीय महाअभियान से जोड़ा जा रहा है ताकि जनता में विशेषकर युवाओं में जागृति आए कि नशा किस प्रकार से उनके स्वास्थ्य एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को खत्म कर प्रगति को बाधित कर रहा है। पुलिस का यह कार्य जन-जागरुकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समुदाय को कानून, असुरक्षा, गलत नीतियों के बारे में जानकारी देना आवश्यक है, ताकि प्रदेशवासी नशा और अपराध मुक्त वातावरण में एक बेहतर जीवन जी सकें।

जागरूकता, संवाद, सहयोग और सुरक्षा है अभियान का मूलमंत्र-नशे के विरुद्ध समुदाय आधारित जन-जागरुकता अभियान में विभिन्न शासकीय विभाग, गैर-सरकारी संगठन ,धर्माचार्य, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि, सभी समुदायों के लोग बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं। मध्यप्रदेश पुलिस गली-गली में जाकर आम जनता से संवाद कर रही है कि कैसे वे नशे से मुक्त रहें और युवा पीढ़ी नशे से दूरी बनाकर अपना भविष्य सुरक्षित करे। यह अभियान स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थलों और डिजिटल माध्यमों के ज़रिए जन-जागृति फैलाने में सहायक सिद्ध होगा। जागरूकता, संवाद, सहयोग और सुरक्षा अभियान का मूलमंत्र है।

बीमा सखी योजना- सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल

'ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा समावेशन हेतु 'बीमा सखी योजना' का विस्तार' महिलाओं को मिलेगा रोजगार, गांवों को सामाजिक सुरक्षा

भोपाल। ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस साझेदारी के तहत, देशभर में स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित महिलाओं को 'बीमा सखी' के रूप में ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त किया जाएगा।यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक सभी के लिए बीमाके दृष्टिकोण एवं आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के अनुरूप है। बीमा सखी योजना महिलाओं को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के साथ-साथ ग्रामीण समुदायों तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त माध्यम बनकर उभरेगी।

बीमा सखियाँ, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, बीमा एजेंट के रूप में कार्य करेंगी और लाखों लोगों के घरों तक किफायती बीमा समाधान पहुंचाने में सक्षम होंगी। बीमा सखियों द्वारा अपने स्थानीय ज्ञान और सामाजिक जुड़ाव के माध्यम से समुदायों को बीमा के महत्व, एलआईसी के उत्पादों और वित्तीय सुरक्षा के बारे में जागरूक करने का काम किया जाएगा।

इस योजना के प्रमुख लाभ

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण - बीमा सखियाँ उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनेंगी।

रोजगार सृजन और महिला श्रम बल में भागीदारी - ग्रामीण स्तर पर महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़ेगी।

लचीला और समावेशी बीमा तंत्र - समुदाय आधारित, भरोसेमंद और किफायती बीमा सेवाएँ सुलभ होंगी।

बीमा सखी योजना, सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को एक सूत्र में पिरोते हुए, भारत के ग्रामीण परिदृश्य में आर्थिक समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में अपनी पहचान बना रही है। इसी सुदृढ़ता के साथ आगे भी इस साझेदारी को राज्य सरकारों के सहयोग, कौशल विकास कार्यक्रमों के समन्वय और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा।

कलाओ में बघेश्वर और मणिधर प्रदर्शनी का शुभारंभ

भोपाल। वीर भारत न्यास द्वारा समुद्र मंथन दिवस पर गुरूवार को रवीन्द्र भवन परिसर में 'हरिहर राष्ट्रीय नाट्य समारोह' के साथ-साथ 'कलाओं में बघेश्वर और मणिधर प्रदर्शनी' का शुभारंभ एवं पुस्तक 'लोक में मणिधर-बघेश्वर' का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया । इस अवसर पर मंत्री कृष्णा गौर, पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा, संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला, मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार श्रीराम तिवारी, संस्कृति संचालनालय संचालक एन पी नामदेव सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

एम्स भोपाल ने आयोजित किया सीपीआर जागरूकता सत्र

भोपाल। कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में एम्स भोपाल आमजन में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने हेतु सामुदायिक सहभागिता पर आधारित कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन कर रहा है। इसी श्रृंखला में बाल रोग विभाग और ट्रॉमा एवं आपातकालीन चिकित्सा विभाग द्वारा भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी (आईएपी) द्वारा 14 से 28 जुलाई तक मनाए जा रहे सीपीआर जागरूकता पखवाड़े के अंतर्गत सागर पब्लिक स्कूल, भोपाल के विद्यार्थियों हेतु सीपीआर एवं आपात प्रतिक्रिया का प्रत्यक्ष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र का उद्देश्य विद्यार्थियों में आपातकालीन स्थितियों से निपटने की समझ, आत्मविश्वास एवं जीवन रक्षक तकनीकों का अभ्यास कराना था, जिससे वे संकट के समय किसी की जान बचा सकें। विशेषज्ञ प्रशिक्षण दल का नेतृत्व डॉ. गिरीश चंद्र भट्ट, डॉ. भूपेश्वरी पटेल एवं डॉ. बाबूलाल सोनी ने किया। सत्र के दौरान विद्यार्थियों को वयस्कों तथा शिशुओं में हृदय गति रुकने की स्थिति में किए जाने वाले सीपीआर का प्रत्यक्ष प्रदर्शन दिखाया गया। साथ ही, सांस की नली में अवरोध (चोकिंग) उत्पन्न होने पर प्राथमिक चिकित्सा द्वारा जीवन रक्षण की विधियाँ भी सिखाई गईं। वैश्विक आँकड़ों के अनुसार, लगभग 70 प्रतिशत हृदयगति रुकने की घटनाएँ अस्पताल के बाहर होती हैं और ऐसे में कोई प्रशिक्षित व्यक्ति यदि तुरंत सहायता करे, तो जीवन बचाया जा सकता है। भारत में इस प्रकार की जानकारी की कमी के कारण, अचानक हृदयगति रुकने के पश्चात जीवित बचने की संभावना 5 प्रतिशत से भी कम है। जबकि यदि प्रारंभिक तीन मिनटों में सीपीआर दिया जाए, तो यह संभावना तीन गुना तक बढ़ जाती है।

इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने कहा, एम्स भोपाल समाज के प्रत्येक वर्ग को जीवन रक्षक ज्ञान प्रदान करने के लिए भी समर्पित हैं। सीपीआर जैसी सरल लेकिन प्रभावी तकनीकें जीवन और मृत्यु के मध्य का अंतर सिद्ध हो सकती हैं। यदि हमारे विद्यार्थी इस ज्ञान को प्राप्त करें, तो वे केवल अपने परिवार नहीं, अपितु समाज के लिए भी रक्षक बन सकते हैं। विद्यालय स्तर पर इस प्रकार के प्रशिक्षण अति आवश्यक हैं।

चलती ट्रेन से गिरी महिला, बोगी-प्लेटफॉर्म के बीच फंसी

ड्रिल मशीन से खोदना पड़ा, 40 मिनट बाद निकाली गई; पानी भरने उतरी थी

अशोकनगर (नप्र)। अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर एक महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई। महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसके गिरने के बाद यात्रियों में से ही किसी ने चेन पुलिंग कर दी। 40 मिनट के रेस्क्यू के बाद महिला को सुरक्षित निकाला जा सका।

घटना गुरुवार सुबह 10 बजे की है। राजस्थान के अलीगढ़-रामपुरा की रहने वाली मधु लक्ष्यकर (32) लालगढ़-पुरी एक्सप्रेस में सवार थी। अशोकनगर रेलवे स्टेशन के एक नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकी तो वह बोतल में पानी भरने उतरी। इतने में ही ट्रेन चल पड़ी।

मधु ने दौड़कर गाड़ी में चढ़ने की कोशिश की लेकिन पैर फिसल गया और वह गिरकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गईं।

रेस्क्यू के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मधु के सिर और पीठ में चोट आई है। मधु लक्ष्यकर अपने परिवार के साथ राजस्थान के सवाई माधोपुर जा रही थी।

पुल का ढांचा गिरने से 4 मजदूर दबे

छतरपुर में एक की हालत गंभीर थी, खजुराहो-ललितपुर रेलवे लाइन पर हो रहा था निर्माण

छतरपुर (नप्र)। छतरपुर जिले के खजुराहो-ललितपुर रेलवे लाइन पर बन रहे एक पुल का ढांचा गुरुवार दोपहर गिर गया। चार मजदूर मलबे में दब गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां अशोक कुशवाहा नाम के मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है।

बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य में लापरवाही की शिकायतें पहले भी की गई थीं, लेकिन राजनगर के अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। यह हादसा दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ, जब खजुराहो-ललितपुर रेलवे लाइन पर केन नदी के पास पहाड़ी बाबन के आगे एक पुल का निर्माण कार्य चल रहा था। तभी अचानक पुल का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर गया और वहां काम कर रहे मजदूर उसकी चपेट में आ गए।मलबे में दबे चार मजदूरों में अरविंद प्रजापति, पांडव, सानुज कुमार, अशोक कुशवाहा घायल हुए हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए मलबे से मजदूरों को बाहर निकाला और तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया।

नीचे काम कर रहे थे मजदूर, ऊपर से जाल गिरा-ग्राम पहाड़ी बावन के गांव के घायल मजदूर अशोक कुशवाहा ने बताया कि रेलवे का काम चल रहा था हम लोग केन नदी के पास पुलिया का काम चल रहा था। हम चार दिन से कम कर रहे थे हम सब से वाले नीचे फ्लोर में काम कर रहे थे ऊपर से जाल गिर गया हम लोग निकल नहीं पाए, हम वहीं दब गए। हम चार लोग ज्यादा घायल हुए हैं हम लोगों को चंद्र नगर अस्पताल लाया गया जहां से प्राथमिक उपचार की बाद जिला अस्पताल भेजा है।

मजदूर बोला- तुरंत मशीनों से बाहर निकाला-घायल अरविंद प्रजापति ने बताया हम लोगों से गलती हो गई। जाल बनाते समय वह हमसे ढीला बंधा। हम लोगों के ऊपर पूरा जाल गिर गया पूरा स्टाफ था कई लोग काम कर रहे थे तुरंत मशीनों की मदद से बाहर निकाला गया।

मौके पर मच गई थी अफरा-तफरी-घटना के बाद निर्माण स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। पुल का ढांचा गिरते ही वहां चीख-पुकार मच गई थी। हादसे की खबर मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू में मदद की। घटना के बाद ग्रामीणों और मजदूर संगठनों ने इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

पहले दी गई थी जानकारी, नहीं हुई कार्रवाई

स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुल निर्माण में सुरक्षा के जरूरी उपाय नहीं अपनाए जा रहे थे। कई बार इसकी जानकारी राजनगर प्रशासन को दी गई थी, लेकिन अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इस लापरवाही का नतीजा आज एक बड़ी दुर्घटना के रूप में सामने आया है।

केंद्र ने मानी मोहन सरकार की मांग, तीन चौथाई गेहूं, एक चौथाई चावल बंटेगा

राशन दुकानों में अब चावल कम, गेहूं अधिक मिलेगा

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में राशन दुकानों में अब चावल के बजाय अधिक गेहूं दिया जाएगा। राज्य सरकार की डिमांड पर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्र के फैसले के बाद अब पीडीएस की दुकानों से पात्र हितग्राहियों को जो खाद्यान्न मिलता है उसमें 75 प्रतिशत गेहूं और 25 प्रतिशत चावल दिया जाएगा। अभी दोनों ही खाद्यान के वितरण का रेशियो 60:40 था जो अब परिवर्तित हो गया है।

प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने तीन दिन पहले दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर इस प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए कहा था। इसके पीछे मंत्री राजपूत ने तर्क दिया था कि एमपी गेहूं उत्पादक राज्य है और यहां भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में गेहूं सही समय पर वितरित नहीं होने से खराब होता है।

इसलिए राज्य सरकार की मांग पर केंद्र फैसला करे। इसके बाद केंद्र के निर्णय पर अब तय हो गया है कि एमपी के राशनकार्ड धारकों को अब चावल के बजाय गेहूं ज्यादा मिलेगा।

मंत्री राजपूत ने बताया कि प्रदेश के पात्र परिवारों को मिलने वाले खाद्यान्न में 75 प्रतिशत गेहूं और 25 प्रतिशत चावल वितरित किया जाएगा।

अभी तक चावल और गेहूं 60:40 के अनुपात में वितरित किया जाता था। जिलों के दौरे पर कई बार नागरिकों द्वारा वर्तमान वितरण व्यवस्था में बदलाव कर गेहूं की मात्रा बढ़ाकर 75 फीसदी और चावल की 25 फीसदी करने की मांग की जाती रही है। इसके चलते केंद्र सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया।

केंद्र का फैसला नीतिगत बदलाव-खाद्य मंत्री राजपूत ने कहा है कि राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय न केवल जनहितैषी है, बल्कि यह केंद्र-राज्य समन्वय का भी सशक्त उदाहरण है। यह दर्शाता है कि यदि मांग व्यावहारिक हो तो नीतिगत बदलाव संभव हैं।

खाद्य मंत्री राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव की मंशानुसार पीडीएस को अधिक पारदर्शी और हितग्राही केंद्रित बनाने के लिए आधार प्रमाणीकरण, डिजिटल वितरण ट्रैकिंग और ई-केवाईसी जैसी आधुनिक तकनीकों को तेजी से लागू किया जा रहा है।

मंत्री राजपूत ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण और सारगर्भित त्वरित निर्णय पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी का आभार व्यक्त किया है।

अब फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए Digilocker अनिवार्य

भोपाल (नप्र)। प्रदेशभर में बी.फ़ार्मा और एम.फ़ार्मा करने वाले छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन से पहले Digilocker पर अकाउंट बनाना अनिवार्य होगा। फार्मेसी काउंसिल की रजिस्ट्रार भव्या त्रिपाठी के अनुसार, जल्द ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया एक विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से शुरू होगी।

यह सॉफ्टवेयर समग्र आईडी और Digilocker अकाउंट से दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करेगा। इनमें स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, डिग्री, डिप्लोमा, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, फोटो सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल होंगे। अभी तक यह पूरी प्रक्रिया मैन्युअल होती थी, जिससे काफी समय लग रहा था। इसकी वजह है पेंडेंसी बढ़ रही थी।

70 प्रतिशत आवेदनों में होती है त्रुटि- अधिकारियों के अनुसार 70 प्रतिशत फॉर्म में त्रुटियां होती है। एक ही फॉर्म में कैंडिडेट्स बताने के बाद भी बार-बार गलतियां करते हैं। जिसके कारण पेंडेंसी बढ़ी है। अधिकतर मामलों में अंग्रेजी में नाम या अन्य विवरण की स्पेलिंग में गलतियां पाई गईं। काउंसिल इस परेशानी से बचने के लिए आधुनिक डिजिटल सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है।

इसके माध्यम से छात्र घर बैठे ऑनलाइन वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। गलती होने पर सॉफ्टवेयर उन्हें इसकी जानकारी देगा। जब तक वेरिफिकेशन पूरा नहीं होगा, तब तक छात्रों से फीस नहीं ली जाएगी। अब तक MP online से आवेदन के दौरान पहले फीस ली जा रही थी। बाद में वेरिफिकेशन होता था। साढ़े 10 हजार तक पहुंच गई थी पेंडेंसी, होता था विवाद प्रदेशभर में बी.फ़ार्मा और एम.फ़ार्मा करने वाले छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। छात्र पिछले दो-ढाई साल से भोपाल स्थित फार्मेसी काउंसिल के चक्कर लगाकर परेशान हो गए। कई बार प्रदर्शन हुए, कुछ छात्र तो नाराजगी में आपा खो बैठे और काउंसिल में तैनात गार्ड से मारपीट तक की।

अशोकनगर में घरों में घुसा पानी, बाढ़ जैसे हालात

● भोपाल, रायसेन समेत कई जिलों में तेज बारिश, मड़ीखेड़ा, बारना डैम के गेट खोले

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने से गुरुवार को भी कई जिलों में कहीं हल्की, कहीं तेज बारिश हो रही है। सुबह 8 बजे शिवपुरी में अटल सागर बांध मडीखेड़ा के दो गेट खोले गए हैं। यहां से 346 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है। इससे पहले रात 12 से 3 बजे तक रायसेन में बारना बांध के 4 गेट एक-एक मीटर खोलकर दस हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया।

भोपाल में सुबह से रिमझिम दोपहर में तेज बारिश होने लगी। इंदौर में भी ऐसा ही मौसम है। रायसेन में तेज बारिश के बाद कई नदी-नाले उफान पर आ गए। अशोकनगर के मुंगावली में 4 घंटे की बारिश में लोगों को घरों में 3 फीट तक पानी भर गया। नदी-नाले उफान पर है। यहां बाढ़ जैसे हालात हैं।

मौसम विभाग ने जबलपुर समेत 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, विदिशा, सीहोर, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, छतरपुर, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, पन्ना, कटनी, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर और उमरिया में भारी बारिश का दौर बना रहेगा। अगले 24 घंटे में इन जिलों में साढ़े 4 इंच तक पानी गिर सकता है।

अशोकनगर के मुंगावली में 4 घंटे बारिश- अशोकनगर जिले के मुंगावली में गुरुवार सुबह करीब 5 बजे से लेकर 9:30 बजे तक लगातार तेज बारिश हुई। चार घंटे की इस बारिश ने शहर के कई इलाकों को जलमग्न कर दिया। खड़िया नाला उफान पर आ गया, जिससे बहादुरपुर रोड के आसपास के घरों में 3 फीट तक पानी भर गया।

गृहस्थी का सामान पानी में डूब गया। कई मोहल्लों की गलियों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। नरखेड़ा गांव जाने वाला रास्ता पूरी तरह से पानी में डूब गया, जिससे यह मार्ग बंद हो गया है। मुंगावली से बीना जाने वाले मार्ग पर कंजिया के पास पुल पर पानी आ गया।

इस बार 7 इंच बारिश ज्यादा

मध्यप्रदेश में इस मानसूनी सीजन में औसत 21.1 इंच बारिश हो चुकी है जबकि अब तक 14.1 इंच बारिश होनी थी। इस हिसाब से 7.3 इंच बारिश ज्यादा हो चुकी है, जो 53 प्रतिशत अधिक है। 3 जिले- निवाड़ी, टीकमगढ़ और श्योपुर में तो कोटा पूरा हो चुका है। इन जिलों में सामान्य से 25 प्रतिशत तक ज्यादा पानी गिर चुका है। ग्वालियर समेत 5 जिले भी बेहतर स्थिति में हैं। यहां 80 से 95 प्रतिशत तक बारिश हो चुकी है। दूसरी ओर, इंदौर और उज्जैन संभाग सबसे पीछे है। इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, बुरहानपुर और आगर-मालवा में 10 इंच से भी कम पानी गिरा है।

निगम अध्यक्ष सूर्यवंशी बोले,भोपाल का नवाब गद्दार था और रहेगा

हमीदिया अस्पताल, कॉलेज-स्कूल के नाम बदलने का प्रस्ताव पास

सदन की बैठक में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे; कुछ देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही

भोपाल (नप्र)। भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में बीजेपी पार्षद विलास राव घाड़गे ने कमिश्नर हरेंद्र नारायण की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कमिश्नर के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाने की बात कही। इसके बाद वे अध्यक्ष की आसंदी के सामने जमीन पर बैठ गए। पार्षद के इस कदम पर एमआईसी मेंबर जगदीश यादव ने आपत्ति ली।

उन्होंने कहा कि कमिश्नर ऐसे नहीं हैं। उनके प्रयास से ही भोपाल देश में दूसरे नंबर पर आया है। इसी मुद्दे पर कांग्रेसी पार्षद भी मैदान में उतर गए। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी, पार्षद मो. सरवर, योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान ने भी कमिश्नर का पक्ष रखा। कुछ देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। इसके बाद अध्यक्ष सूर्यवंशी ने पार्षद घाड़गे को समझाकर उठने को कहा। हंगामे के बाद 1 घंटे का प्रश्न काल शुरू किया गया।

बैठक में पुराना अशोका गार्डन का नाम राम बाग करने, 80 फीट रोड स्थित विवेकानंद चौराहे का नाम विवेकानंद चौक करने का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके अलावा 6 विसर्जन कुंड बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। पुराने शहर स्थित ओल्ड अशोका गार्डन का नाम बदलकर राम बाग और विवेकानंद पार्क के पास चौराहे का नाम विवेकानंद चौक किया जाएगा।

बीजेपी पार्षद देवेंद्र भार्गव के हमीदिया अस्पताल, कॉलेज और स्कूल के नाम बदलने का प्रस्ताव पास होते ही सदन में जोरदार हंगामा हुआ। हंगामे के बीच सदन का 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। इसी बीच बैठक में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। हमीदिया अस्पताल, कॉलेज और स्कूल का नाम बदलने को लेकर दोनों दलों के पार्षदों के बीच जमकर नोकझोंक हुई।

नाम बदलने को लेकर पार्षद ने दिए थे प्रस्ताव

वार्ड-69 के पार्षद सूर्यकांत गुप्ता ने ओल्ड अशोका गार्डन का नाम बदले जाने का प्रस्ताव दिया है। 26 मई-24 को पुराना अशोका गार्डन सुधार समिति ने साधारण सभा के बाद ओल्ड अशोका गार्डन का नाम राम बाग करने का प्रस्ताव दिया था।

80 फीट रोड स्थित विवेकानंद पार्क, अशोका गार्डन के पास चौराहे का नाम विवेकानंद चौक करने का प्रस्ताव आएगा। यह प्रस्ताव भी पार्षद गुप्ता ने दिया था। चौराहे की पहचान के लिए रहवासी नवीन नामकरण की मांग कर रहे थे।

बीजेपी पार्षद भार्गव के हमीदिया अस्पताल, कॉलेज और स्कूल के नाम बदलने का प्रस्ताव सदन से पास होते ही जोरदार हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगे। बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच एक जमकर नोकझोंक हुई। इस बीच निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा- भोपाल का नवाब गद्दार था, गद्दार है और गद्दार रहेगा।

नाम बदलने का प्रस्ताव पास

हंगामे के बीच अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने पार्षद देवेंद्र भार्गव के हमीदिया अस्पताल के नाम बदलने के प्रस्ताव को पास कर दिया। इस दौरान सदन में पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस पार्षद आमने सामने हो गए। उनके बीच जमकर नोकझोंक हुई। एक कांग्रेस पार्षद द्वारा बीजेपी पार्षदों से अभद्रता भी की गई।

ओल्ड अशोका गार्डन का नाम बदलने का प्रस्ताव आया था : महापौर

इस मामले में महापौर मालती राय ने मीटिंग के दौरान साफ किया कि अशोका गार्डन में कई बड़े इलाके शामिल हैं। इनमें से सिर्फ ओल्ड अशोका गार्डन का नाम बदलने का प्रस्ताव है। अन्य इलाकों के नाम यथावत रहेंगे।

पिता के नाम से सड़क के नाम का प्रस्ताव, पार्षद बेटी के छलके आंसू- नगर निगम की बैठक में पूर्व विधायक, बीजेपी के जिलाध्यक्ष रहे रमेश शर्मा गुट्टू भैया के नाम पर 80 फीट की रोड का नाम रखने का प्रस्ताव पार्षद गीता प्रसाद माली ने रखा। इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात निगम अध्यक्ष ने कही। पार्षद प्रियंका मिश्रा ने कहा कि मैं परिषद की आभारी हूं। यदि हमीदिया कॉलेज का नाम भी स्व. रमेश शर्मा जी के नाम से रखा जाए तो आभारी रहूंगी। प्रियंका स्व. शर्मा की बेटी हैं। इस दौरान उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। विलास राव घाड़गे ने एक पार्क का नाम पूर्व विधायक, बीडीए अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ सिंह के नाम से करने का प्रस्ताव रखा। इस पर अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने आगे की कार्रवाई करने के आदेश आसंदी से दिए।

इस दौरान सावित्री बाई फुले की प्रतिमा को भी शहर में अच्छे स्थान पर लगाने के आदेश दिए गए। पार्षद प्रताप वारे ने बाग मुगालिया बस स्टॉप का नाम डॉ. भीमराव अंबेडकर रखने का प्रस्ताव रखा। पार्षद आरती अनेजा ने वार्ड-32 में टीटी नगर स्थित काली मंदिर के पास की सड़क का नाम योगाचार्य श्रीकृष्ण मोहन गांगुली के नाम से करने का प्रस्ताव रखा।

विवेकानंद चौराहे का नाम अब विवेकानंद चौक से होगा

80 फीट रोड स्थित विवेकानंद चौराहे का नाम विवेकानंद चौक करने का प्रस्ताव एमआईसी मेंबर वाणी ने रखा। पार्षद सूर्यकांत गुप्ता ने समर्थन किया। इस प्रस्ताव का बीजेपी के पार्षदों ने समर्थन किया। चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से पास कर दिया गया।

पुराना अशोका गार्डन का नाम अब 'राम बाग' होगा, बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पास- पुराना अशोका गार्डन का नाम राम बाग करने का प्रस्ताव एमआईसी मेंबर अशोक वाणी ने रखा। बीजेपी पार्षद सूर्यकांत गुप्ता ने समर्थन किया। उन्होंने बताया कि मैंने ही प्रस्ताव एमआईसी को दिया था। कॉलोनी के लोग चाहते हैं कि इसे राम बाग किया जाए। पूर्व में जब बाग थे, तब इसका नाम राजा राम का बाग था। इसके चलते ही रहवासियों ने प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव का बीजेपी पार्षदों ने समर्थन दिया।

दिल्ली से ठगी करके फरार दो सब इंस्पेक्टर इंदौर से पकड़ाए

पकड़े गए ठगों में एक महिला सब इंस्पेक्टर शामिल

इंदौर। दिल्ली में ठगी के मामले में फरार एक पुरुष और एक महिला सब इंस्पेक्टर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये दोनों सावेर रोड स्थित एमरल्ड सिटी में छुपकर फरारी काट रहे थे। पकड़े गए आरोपी एसआई अंकुर मलिक के साथ महिला एसआई की पहचान अभी उजागर नहीं की गई। पुलिस के अनुसार, इनके पास से लगभग 1 किलो 20 ग्राम सोने के आभूषण और 10 लाख रुपये से ज्यादा नकद भी बरामद किए गए। ये दोनों दिल्ली में बंटी-बबली की तर्ज पर ठगी की वारदातों में शामिल थे। ये लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहे थे। दिल्ली से फरार होने के बाद दोनों के पीछे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की साइबर क्राइम पुलिस लगी थी। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए इनकी लोकेशन ट्रेस की और आखिरकार इंदौर में होने की पुष्टि के बाद दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया।

दिल्ली में कुछ महीनों पहले दो सब इंस्पेक्टर ठगी के मामले में सीज किए बैंक अकाउंट से मोटी रकम निकालकर फरार हो गए थे। काफी समय तक पुलिस को भी इस बारे में पता नहीं चला। इस ठगी का पता पुलिस को अप्रैल महीने में लगा। मामले की जानकारी होते ही विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आनन-फानन में जांच शुरू की। जांच में दो सब इंस्पेक्टरों की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जो कि धोखाधड़ी के बाद से ही फरार चल रहे थे।

अब इनसे दिल्ली में पूछताछ- यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने इंदौर पुलिस के सहयोग से की। जांच में सामने आया कि दोनों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए इंदौर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मकान किराए पर लिया था और खुद को अलग पेश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस अब इन दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, ताकि यह पता चल सके कि ठगी के मामलों में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और कितनी वारदातों को अंजाम दिया।

इस मामले में तीन पहले पकड़े

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के माध्यम से आरोपियों की लोकेशन इंदौर के बाणगंगा इलाके में मिली थी। आरोपियों ने ठगी के माध्यम से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है। दिल्ली में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। दोनों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिये फ्रीज अकाउंट में मोटी रकम ट्रांसफर की। पूछताछ में और भी चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है। मामले में 3 अन्य आरोपियों को दिल्ली पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। पूछताछ कर ठगी के पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा।

दिल्ली पुलिस ने आतंकी संगठन से जुड़े आकाशदीप सिंह को इंदौर से पकड़ा

पंजाब के थानों पर हमला करने का आरोपी हीरा नगर क्षेत्र में छुपा

इंदौर। पंजाब के थाने में बम से हमला करने वाले फरार आरोपी आकाशदीप सिंह को दिल्ली पुलिस ने हीरा नगर इलाके से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है आर्म्स एक्ट और अन्य मामले में भी वह फरार था। पिछले दिनों पंजाब में कई थानों पर आतंकवादियों ने हैंड ग्रेनेड से हमला किया और फरार हो गए थे।

इस बीच दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी पंजाब के बटाला थाने पर ग्रेनेड से हमला करने वाला आरोपी आकाशदीप इंदौर के हीरा नगर थाना क्षेत्र में छुपा है। जिस पर से स्थानीय पुलिस के सहयोग से दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुप्त रूप से यह ऑपरेशन चलाकर आकाशदीप को पकड़ा है। इस पूरे मामले में एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने बताया कि आर्म्स एक्ट और अन्य प्रकरण में फरार आरोपी को इंदौर पुलिस के सहयोग से ही गिरफ्तार किया गया। वहीं दिल्ली पुलिस द्वारा कुछ ज़्यादा जानकारी शेयर नहीं की गई है इंदौर पुलिस से सहयोग की मांग की गई थी, उसके अनुसार पुलिस का सहयोग किया गया।

अमित सिंह ने कहा कि अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या वह किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य था। हमें जहां तक जानकारी है उस पर आर्म्स एक्ट के मामले थे और इसी मामले में उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ यहां कोई मामला दर्ज नहीं है और न उसके अपराध के बारे में हमें कोई जानकारी है। इसलिए अभी यह कहा नहीं जा सकता कि उसके ऊपर क्या मामले हैं!

आग बुझाने में दो घंटे से ज्यादा लगे

भोपाल (नप्र)। हनुमानगंज गल्ला बाजार में ड्राई फ्रूट्स की दुकान ज्ञानचंद एंड संस में मंगलवार रात भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में दो घंटे से ज्यादा वक्त लगा। गोविंद गार्डन निवासी दुकान संचालक अमित बत्रा ने बताया कि रात साढ़े नौ बजे वह दुकान बंद कर घर लौटे थे। करीब साढ़े ग्यारह बजे परिचित का कॉल आया कि दुकान से धुआं निकल रहा है।

कुछ ही देर में आग की सूचना मिली। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और शटर ठंडा कर तोड़ा। रात दो बजे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बत्रा ने बताया कि वे दिल्ली, मुंबई और तमिलनाडु से ड्राई फ्रूट्स मंगाते थे।

नुकसान कितना हुआ, इसका आकलन अब तक नहीं हो सका है। प्रत्यक्षदर्शी विवेक साहू ने बताया कि जलने की गंध आने पर बाहर निकले तो दुकान के बाहर भीड़ थी और आग की लपटें उठ रही थीं।

रामकृष्ण कुसमारिया पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष बने, पदभार ग्रहण किया

पूर्व मंत्री बिसेन की बेटी बनीं मौसम सदस्य, एमपी में पिछड़े वर्ग के हैं दो-दो आयोग

भोपाल (नप्र)। इससे पहले 13 दिसंबर 2023 को डॉ. रामकृष्ण कुसमारिया ने मप्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। इससे पहले 13 दिसंबर 2023 को डॉ. रामकृष्ण कुसमारिया ने मप्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था।

पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमारिया को मप्र पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इस आयोग में पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन को सदस्य बनाया गया है।

बता दें, मप्र पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन सितंबर 2021 में हुआ था। 2 सितंबर 2021 को जारी अधिसूचना के अनुसार इस आयोग का कार्यकाल दो साल के लिए तय किया गया था और आवश्यकता अनुसार कार्यकाल बढ़ाने की बात कही गई थी। इससे पहले 3 सितंबर 2021 को पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को मप्र पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। रामकृष्ण कुसमारिया इस आयोग के दूसरे अध्यक्ष हैं। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन जिस आयोग के अध्यक्ष रहे उनकी बेटी को उसी आयोग में सदस्य बनाया गया है।

मप्र में ओबीसी वर्ग के दो-दो आयोग- मप्र में ओबीसी वर्ग के दो-दो आयोग हैं। मप्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया गया था। कमलनाथ सरकार में वरिष्ठ अधिवक्ता जेपी धनोपिया को साल 2020 में मप्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन बाद में कमलनाथ सरकार गिर गई। हालांकि धनोपिया का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था ऐसे में वे कोर्ट चले गए। इधर, मप्र में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का मामला भी कोर्ट पहुंच गया। इसके बाद सितंबर 2021 में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मप्र पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन कर गौरीशंकर बिसेन को अध्यक्ष बनाया और कोर्ट में ओबीसी को 27 प्रतिशत की रिपोर्ट पेश की। मप्र में 2023 के विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले 6 अक्टूबर 2023 को डॉ रामकृष्ण कुसमारिया को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया था। हालांकि उन्होंने विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद दिसंबर में पदभार ग्रहण किया था।